वर्ष 12 • अंक 291 • 14 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शुक्रवार 24 जनवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

अजय त्यागी ▶▶ पृष्ठ 14

एआई से सोशल मीडिया पर नजर रखेगा सेबी

केपी सिंह ▶▶ पृष्ठ 3

13,000 करोड़ रुपये निवेश करेगी डीएलएफ

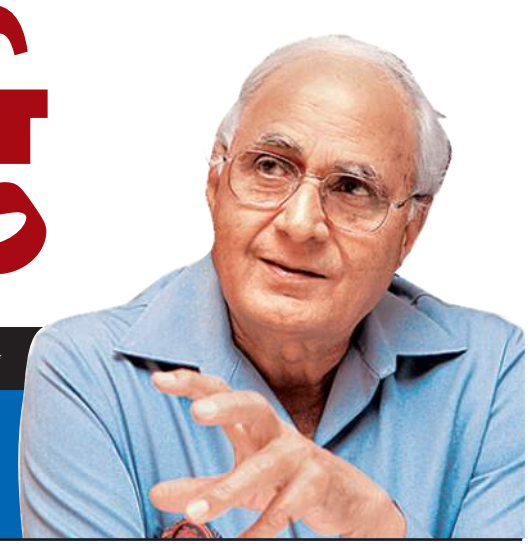

डॉलर रु. 71.30 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 79.10 ▲ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 39863 ▼ 53 रुपये | सेंसेक्स 41386.40 ▲ 271.00 | निफ्टी 12180.30 ▲ 74.40 | निफ्टी फ्यूचर्स 12201.00 ▲ 20.70 | ब्रेंट क्रूड 61.70 डॉलर ▼ 0.50 डॉलर

एक नज़र

एफपीआई के अल्पावधि निवेश की सीमा बढ़ी

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अल्पावधि के निवेश की सीमा बढ़ा दी। अगर वे स्वेच्छा से निवेश की योजना पहले घोषित करते हैं तो उनके निवेश की पात्रता दोगुनी होगी। दो अलग-अलग अधिसूचना के जरिये केंद्रीय बैंक ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अब अपने पोर्टफोलियो का 30 फीसदी केंद्र व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में कर सकेंगे, जो पहले 20 फीसदी था। इसी तरह कॉरपोरेट बॉन्ड में भी अल्पावधि निवेश की सीमा अब पोर्टफोलियो के 30 फीसदी के बराबर होगी, जो पहले 20 फीसदी थी। पृष्ठ 3

सीपीएसई ईटीएफ की आएगी सातवीं किस्त

सरकार सीपीएसई ईटीएफ की सातवीं किस्त से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक रकम जुटाने की योजना बना रही है। बाजार सूत्रों के अनुसार ईटीएफ की यह किस्त माह के अंत तक आ सकती है। सीपीएसई ईटीएफ निर्गम एंकर निवेशकों के लिए 30 जनवरी को खुल सकता है। अगले दिन खुदरा और अन्य निवेश इसमें निवेश कर सकते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के ईटीएफ के पोर्टफोलियो में चुनिंदा शेयर शामिल हैं, जिनमें अधिकांश ऊर्जा एवं तेल क्षेत्र के हैं।

इंजन आपूर्ति में देरी से कुछ उड़ानें रद्द : गोएयर

किफायती हवाई सेवा उपलब्ध कराने वाली विमानन कंपनी गोएयर ने गुरुवार को कहा कि ठप पड़ी एयरबस ए320 नियो विमानों और स्पेयर इंजन की उपलब्धता नहीं होने के कारण उसने 9 मार्च तक के लिए अपनी कुछ उड़ानों को निलंबित कर दिया है। विमानन कंपनी ने कहा कि उसे अपने नेटवर्क की कुछ उड़ानों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि कंपनी ने निलंबित की जाने वाले उड़ानों की संख्या नहीं बताई है। सूत्रों ने संकेत दिए कि रोजाना 20 से 30 उड़ानें निलंबित हो सकती है। पृष्ठ 2

एफपीओ से पहले 1,400 करोड़ रुपये जुटाए

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने गुरुवार को कहा कि एफपीओ निर्गम से पहले ही उसने 1,400 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। इनमें से 607 करोड़ रुपये से कर्ज का भुगतान किया जाएगा। कंपनी का एफपीओ निर्गम 24 जनवरी को खुलेगा और 28 जनवरी को बंद होगा।

आज का सवाल

क्या ऊंचे लेनदेन पर आधार लेने से कालेधन पर लगेगी रोक

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्यों पर बढ़ेगा दबाव?	हां	87.50%
	नहीं	12.50%

आरबीआई से मांगा अंतरिम लाभांश

सरकार ने मांगे 10 हजार करोड़ रुपये, आरबीआई ने अभी नहीं किया कोई निर्णय

सोमेश झा
नई दिल्ली, 23 जनवरी

केंद्र सरकार ने अपना राजकोषीय घाटा कम करने के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश मांगा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

यह लगातार तीसरा मौका है जब केंद्र ने आरबीआई से अंतरिम लाभांश की मांग की है। कर संग्रह और विनिवेश प्राप्तियों में कमी के कारण सरकार के लिए अपने राजस्व लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी जिसमें केंद्रीय बैंक से मिलने वाले अंतरिम लाभांश को शामिल किया जा सकता है। हालांकि आरबीआई को अभी सरकार की मांग पर अंतिम फैसला करना है। 15 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाली आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की बैठक में इस बारे में फैसला किया जा सकता है। फरवरी बैठक से पहले वित्त मंत्री आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित कर सकती हैं। 2018-19 में आरबीआई ने केंद्र सरकार को 28 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था। इसकी घोषणा भी फरवरी 2019 में बजट के बाद हुई बोर्ड बैठक में की गई थी।

पिछले साल आरबीआई ने बैलेंस शीट की छमाही ऑडिट की व्यवस्था शुरू की थी ताकि यह तय किया जा सके कि वह सरकार को कितना अंतरिम लाभांश दे सकता है। हालांकि बैंक के हिसाब किताब का समवर्ती ऑडिट तिमाही आधार पर किया जाता है लेकिन यह पहला मौका था जब आरबीआई का बोर्ड स्तर पर वैधानिक ऑडिट किया गया था। पिछले साल आरबीआई ने कहा था कि सीमित ऑडिट समीक्षा के आधार पर उसने केंद्र सरकार को 28 हजार करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश देने का फैसला किया है। आरबीआई के सरकार को अंतरिम लाभांश देने की व्यवस्था 2016-17 में शुरू हुई थी। तब केंद्र को 10 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे।

आरबीआई का वित्त वर्ष जुलाई से जून के बीच होता है जबकि केंद्र सरकार का वित्त वर्ष अप्रैल से मार्च होता है। केंद्रीय बैंक अगस्त में अंतिम बैलेंस शीट तैयार करता है और इससे पहले ही केंद्र सरकार उससे अंतरिम लाभांश मांगने लगती है। इस अनियमितता को दूर करने के लिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अगुआई में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने सुझाव दिया कि वित्त वर्ष 2020-21 से आरबीआई का वित्त वर्ष भी सरकार की तरह अप्रैल से मार्च तक होना चाहिए। समिति के अनुसार अंतरिम लाभांश असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। लेकिन साथ ही कहा था कि आरबीआई के अपना वित्त वर्ष बदलने के बाद भी आने वाले वर्षों में यह चलन जारी रह सकता है। इससे सरकार के पास इस बार आरबीआई से अंतरिम लाभांश मांगने की गुंजाइश है।

वित्त वर्ष#	लाभांश (करोड़ रुपये में)	अंतरिम लाभांश (करोड़ रुपये में)
2016-17	65,876	0
2017-18	30,659	10,000
2018-19	40,000	28,000
2019-20*	1,47,987	10,000

*10,000 करोड़ रुपये की राशि सरकार ने अंतरिम लाभांश के रूप में मांगी है

#यह सरकार का वित्त वर्ष है जो अप्रैल-मार्च की अवधि है। आरबीआई का वित्त वर्ष जुलाई-जून होता है।

स्रोतः राज्य सभा

एजीआर में देरी पर भी नहीं होगी सख्ती

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 23 जनवरी

- एयरटेल और वोडफोन आइडिया को मिली फौरी राहत
- दूरसंचार विभाग ऑपरेटरों की याचिका पर अदालत में सुनवाई तक करेगा इंतजार
- जियो ने 195 करोड़ रुपये एजीआर बकाया चुकाया

दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को अंतरिम राहत देते हुए कहा है कि अगर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तय समय तक बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) चुका पाने में नाकाम रहती हैं तो वह उनके खिलाफ तत्काल 'प्रतिरोधी' कदम नहीं उठाएगा। शीर्ष अदालत ने गत 24 अक्टूबर के अपने फैसले में इन कंपनियों को 23 जनवरी तक एजीआर मद में 1.47 लाख करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने को कहा था।

भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सरकार से कहा है कि वे एजीआर बकाये पर शीर्ष अदालत के फैसले का पालन करेंगी लेकिन इस राशि का भुगतान करने के पहले वे इस फैसले के खिलाफ दायर 'संशोधन' याचिका पर अगले हफ्ते होने वाली सुनवाई तक इंतजार करेंगी।

दूरसंचार विभाग के लाइसेंसिंग वित्त नीति प्रकोष्ठ ने विभिन्न दूरसंचार सर्किल के संचार लेखा नियंत्रक से कहा है कि उन्हें इन दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ सख्ती नहीं करनी चाहिए। उसने कहा है कि इन लाइसेंसधारक कंपनियों ने पहले ही दूरसंचार विभाग के मुख्यालय को बकाया भुगतान के बारे में सूचित कर दिया है। बकाया भुगतान के लिए विभाग ने 23 जनवरी की समय-सीमा रखी हुई है। इस बारे में विभाग शुक्रवार को शाम पांच बजे एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट भी रखेगा। एक अधिकारी ने कहा, 'दूरसंचार कंपनियों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई का हम इंतजार करेंगे। उसके बाद ही हम एजीआर बकाये की वसूली के बारे में अपना अगला कदम तय करेंगे।'

21 जनवरी को उच्चतम न्यायालय दूरसंचार कंपनियों की तरफ से दायर संशोधन याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। उसने कहा था कि एजीआर के बकाया भुगतान के लिए अधिक वक्त दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर वह विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुआई वाले पीठ ने कहा था कि ताजा अपील को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इस बीच दूरसंचार क्षेत्र की अपेक्षाकृत नई कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने बकाया एजीआर के मद में 195 करोड़ रुपये दूरसंचार विभाग के पास जमा कर दिए हैं।

सेंसेक्स 271 अंक मजबूत : बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स गुरुवार को 271 अंक बढ़कर बंद हुआ। एलऐंडटी, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के शेयरों में तेजी के दम पर बाजार मजबूत हुआ। उतार-चढ़ाव वाले कारोबार में तीस शेयरों वाला सेंसेक्स 271.02 अंक की तेजी के साथ 41,386.40 पर बंद हुआ। निफ्टी 73.45 अंक चढ़कर 12,180.35 पर बंद हुआ।

मंत्री नहीं होता तो एयर इंडिया के लिए बोली लगाता: पीयूष गोयल

भाषा
दावोस, 23 जनवरी

कर्ज बोझ तले दबी सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया की विनिवेश की तैयारियों के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि अगर वह मंत्री नहीं होते तो एयर इंडिया के लिए बोली जरूर लगाते। एयर इंडिया काफी समय से घाटे में चल रही है और अब सरकार इसकी विविनेश प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगी है।

एयर इंडिया, बीपीसीएल और अन्य कंपनियों के प्रस्तावित विनिवेश से जुड़े सवाल पर गोयल ने कहा कि पहले कार्यकाल में हमारी सरकार को ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जो काफी बुरे हाल में थी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को ठीक रास्ते पर लाने के लिए कई कदम उठाए गए। यदि सरकार पहले इन बहुमूल्य कंपनियों का विनिवेश करती तो अच्छा मूल्य नहीं मिलता। गोयल ने विश्व आर्थिक मंच के 'भारत: रणनीतिक परिदृश्य' सत्र में कहा, 'यदि मैं आज मंत्री नहीं होता तो मैं एयर इंडिया के लिए बोली लगाता। इसके दुनिया भर में कुछ बेहतरीन द्विपक्षीय समझौते हैं। इस लिहाज से यह किसी सोने की खान से कम नहीं है।'

पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

उन्होंने कहा, 'भारत ऐसा देश है, जहां आपके पास समान अवसर है और आप ईमानदारी से काम कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बैंकों के खुद के आय-व्यय खातों को ठीकठाक करना और बैंकों को मजबूत बनाना एक अच्छा काम है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज और अन्य समस्याओं को ठीक करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आरसेप पर गोयल ने कहा कि यह असंतुलन वाला व्यापार समझौता है, जो आठ साल पहले निर्धारित आरसेप (आरसीईपी) के सिद्धांतों को पूरा नहीं करता है। इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि भारत के आरसेप देशों में पहले से ही 10 आसियान देशों और जापान एवं कोरिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं।

आधार-पैन नहीं तो कटेगा 20 फीसदी वेतन

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 23 जनवरी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के मुताबिक अगर आप नियोक्ता को अपना स्थायी खाता संख्या (पैन) या आधार देने में नाकाम रहते हैं तो आपके वेतन में से 20 फीसदी राशि कर के रूप में काट ली जाएगी। यह नया नियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका वेतन कर योग्य है।

यह नियम 16 जनवरी से लागू हो गया है। इसका मकसद स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) भुगतान और इस श्रेणी से होने वाली आय पर नजर रखना है। 2018-19 के दौरान कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह में इसका हिस्सा 37 फीसदी था।

वेतन पर टीडीएस से जुड़े 86 पन्नों के परिपत्र में सीबीडीटी ने आय कर कानून की धारा 206एए के तहत कर्मचारियों के लिए पैन या 12 अंकों की आधार संख्या की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। इस परिपत्र में कहा गया है, 'कानून की धारा 206एए के तहत अगर कोई कर्मचारी कोई पैसा या राशि या आय प्राप्त करता है, जिस पर कर कटता है, तो उसके लिए पैन या आधार देना अनिवार्य है।' अगर कर्मचारी पैन/आधार की जानकारी देने में नाकाम रहता है तो उसे कर की ऊंची दर देनी होगी। आय कर प्रावधान में यह दर 20 फीसदी रखी गई है।

नियोक्ता को तीनों परिस्थितियों में कर की राशि तय करनी होगी और टीडीएस की ऊंची दर लागू करनी होगी। अलबत्ता, अगर कर्मचारी की आय कर सीमा से कम है तो उस पर कोई कर नहीं काटा जाएगा। जिन कर्मचारियों का वेतन कर योग्य सीमा से अधिक है, तो नियोक्ता लागू दरों के आधार पर औसत आय कर की गणना करेगा।

तीन अलग-अलग परिस्थितियों में कर की गणना को स्पष्ट करते हुए परिपत्र में कहा गया है कि अगर गणना से निकाली गई दर 20 फीसदी से कम है तो कर कटौती 20 फीसदी की दर से की जाएगी। इसी तरह अगर औसत दर 20 फीसदी से अधिक है तो कर औसत दर के हिसाब से काटा जाएगा। अगर ऊंची दर पर कर कटौती की जाती है तो कर्मचारी को 4 फीसदी की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर नहीं देना होगा। सीबीडीटी का कहना है कि चूंकि कर रिटर्न भरते समय टीडीएस प्रमाणपत्र देने की जरूरत खत्म कर दी गई है, इसलिए पैन या आधार के अभाव में कर कटौती पर क्रेडिट देने में मुश्किल आ रही है। इसलिए नियोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे फॉर्म 24क्यू में उन सभी कर्मचारियों का सही पैन या आधार दें जिनके वेतन में कर कटौती की गई है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

- पैन या आधार की जानकारी देना अनिवार्य
- सीबीडीटी के दिशानिर्देश इसी वित्त वर्ष से होंगे लागू
- कर योग्य वेतन वाले सभी कर्मचारी आएंगे दायरे में

महंगे गहनों या अन्य लेनदेन के लिए देना होगा आधार!

वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर से रत्न एवं आभूषण समेत ज्यादा रकम वाले लेनदेन पर सख्ती करने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में केंद्र सरकार विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है जिनमें ऐसे लेनदेन के साथ आधार क्रमांक या अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज मुहैया कराने को कहा जा सकता है। इसके साथ ही रत्न एवं आभूषण विक्रेताओं को धनशोधन निषेध कानून (पीएमएलए) की रिपोर्टिंग जरूरत के दायरे में शामिल किए जाने का भी प्रस्ताव है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि इस बारे में शुरुआती चर्चा हो चुकी है औ अंतिम निर्णय आम बजट में लिया जा सकता है या इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है। सभी स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़े जाने के बाद इस पहल को महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। चूंकि किसान यह तर्क दे रहे हैं कि उनके पास पैन नहीं हैं, इसलिए कई मामलों में उनके द्वारा की जाने वाली खरीदारी को जांच के दायरे में लाने में समस्या पैदा हुई है। ऐसे सौदों से आधार जोड़ने से ऊंचे मूल्य वाले सभी लेनदेन पर बेहतर तरीके से नजर रखने में मदद मिलेगी। पृष्ठ 6

खबरों में रहे स्टॉक

लार्सन ऐंड टुब्रो

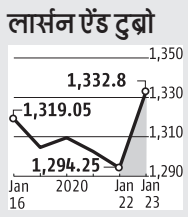

वित्त वर्ष 2020 के लिए ऑर्डर प्रवाह का अनुमान 10-12 फीसदी पर बरकरार

₹ 1,294.25 पिछला बंद भाव
₹ 1,332.80 आज का बंद भाव
▲ 2.98 %

वेस्टलाइफ डेवलपमेंट

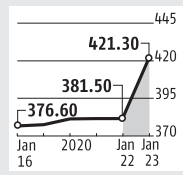

तीसरी तिमाही में सेम स्टोर सेल ग्रोथ 9.2 फीसदी रही

₹ 381.50 पिछला बंद भाव
₹ 421.30 आज का बंद भाव
▲ 10.43 %

एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक

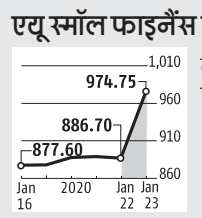

तीसरी तिमाही में एनपीए घटकर 1 फीसदी हुआ

₹ 886.70 पिछला बंद भाव
₹ 974.75 आज का बंद भाव
▲ 9.93 %

गोदरेज प्रॉपर्टीज

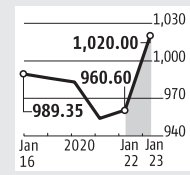

निफ्टी रियल्टी सूचकांक में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 960.60 पिछला बंद भाव
₹ 1,020.00 आज का बंद भाव
▲ 6.18 %

पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस

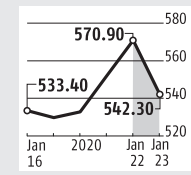

तीसरी तिमाही में शुद्ध ब्याज मार्जिन घटकर 2.98 फीसदी रहा

₹ 570.90 पिछला बंद भाव
₹ 542.30 आज का बंद भाव
▼ 5.01 %

संक्षेप में

मोंडलीज ने निपटाया कर विवाद

कैडबरी चॉकलेट बनाने वाली मोंडलीज इंडिया ने 400 करोड़ रुपये का भुगतान कर विवाद का निपटान कर दिया है। गुरुवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस ने साल 2011 में कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की थी, जो उत्पाद कर छूट का फायदा उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी में नई इकाई को लेकर था। कंपनी ने कथित तौर पर किसी खास इलाके से संबंधित छूट का दुरुपयोग किया है। हिमाचल में इकाई लगाने वाली कंपनियों को उत्पाद कर से 10 साल के लिए छूट मिलती है। *एजेंसियां*

ओबीसी का शुद्ध लाभ 39 फीसदी उछला

सार्वजनिक क्षेत्र के ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) ने कहा कि उसका शुद्ध लाभ दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में 39.11 फीसदी उछलकर 201.66 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। मुख्य रूप से फंसा कर्ज कम होने से बैंक का मुनाफा बढ़ा है। बैंक का विलय अब पंजाब नैशनल बैंक में होने जा रहा है। *भाषा*

परिसंपत्ति में हिस्सा घटाएगी एंजी

कंपनी 12 सौर परियोजनाओं में 74 फीसदी हिस्सेदारी एडलवाइस को बेचेगी

श्रेया जय
नई दिल्ली, 23 जनवरी

फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी एंजी भारत में अपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में बहुलांश हिस्सेदारी की बिक्री एडलवाइस इन्फ्रास्ट्रक्चर यील्ड प्लस (ईआईवाईपी) और अपनी पोर्टफोलियो कंपनी सेकुरा एनर्जी को करेगी। एंजी भारत में 1,500 मेगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता का परिचालन करती है। कंपनी ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर कहा है कि वह कुल 813 मेगावॉट क्षमता की 12 सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 74 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी।

इस सौदे से एंजी को अपना ऋण बोझ 40 करोड़ यूरो तक घटाने में मदद मिलेगी। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि यह सौदा 2020 की पहली छमाही तक पूरा होने की उम्मीद है।

एंजी के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी पाउलो अल्मिरेंटे ने कहा, 'इस लेनदेन से हमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपने रणनीतिक मॉडल को रफ्तार देने में मदद मिलेगी और काफी गतिशील भारतीय सौर बाजार में निवेश के लिए रकम उपलब्ध होगी।'

अक्षय ऊर्जा

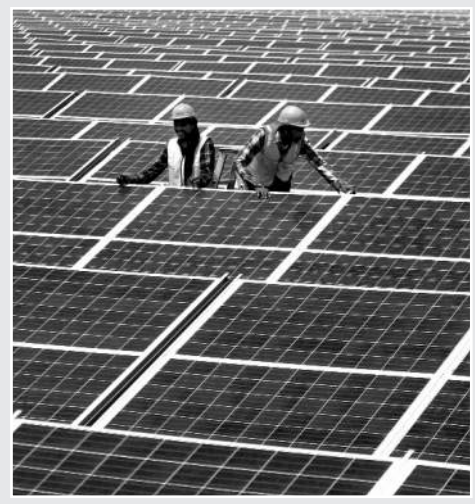

- एंजी भारत में 1,500 मेगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता का परिचालन करती है
- इस सौदे से एंजी को अपना ऋण बोझ 40 करोड़ यूरो तक घटाने में मदद मिलेगी
- कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि यह सौदा 2020 की पहली छमाही तक पूरा होने की उम्मीद है
- एंजी की पवन ऊर्जा परियोजनाएं तमिलनाडु एवं गुजरात हैं जबकि उसकी सौर ऊर्जा परियोजनाएं राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात में हैं

एंजी ने कहा कि यह सौदा कंपनी की डीबीएसओ यानी विकास, निर्माण, साझेदारी एवं परिचालन रणनीति का हिस्सा है। कंपनी ने कहा, 'एंजी अन्य तमाम देशों की तरह भारत में अपनी अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता तैयार करने के लिए उसके डिजाइन, वित्त पोषण एवं निर्माण में अपनी पूरी इंजीनियरिंग दक्षता का इस्तेमाल करती है। क्षमता तैयार होने पर एंजी उस परिसंपत्ति में आंशिक हिस्सेदारी बेच देती है और परिचालन एवं रखरखाव में बरकरार रहती है।'

एंजी अपने मौजूदा और भविष्य के सौर संयंत्रों के विकास, निर्माण एवं परिचालन का इंचार्ज बरकरार रहेगी। ईआईवाईपी के प्रमुख सुबाहु चोरडिया ने कहा, 'ईआईवाईपी को भविष्य में विकसित होने वाली गुणवत्तायुक्त सौर परिसंपत्तियों और समझौते के तहत एंजी द्वारा निर्मित संयंत्रों को ऐक्सेस करने का फायदा मिलेगा।

इंजन उपलब्ध न होने से उड़ान घटाएगी गोएयर

अनीश फडणीस
मुंबई, 23 जनवरी

प्रमुख विमानन कंपनी गोएयर अपने एयरबस ए320 नियो विमानों के खड़े होने और अतिरिक्त इंजन उपलब्ध न होने के कारण उड़ानों की समय-सारणी में 9 मार्च तक बदलाव करने जा रही है।

विमानन कंपनी ने आज कहा कि उसके नेटवर्क में शामिल कुछ उड़ानों तत्काल बंद करने के लिए दबाव दिया गया है। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया है कि कितनी उड़ानों को रद्द की गई है लेकिन सूत्रों का कहना है कि रोजाना 20 से 30 उड़ानों की कटौती की जाएगी। गोएयर रोजाना 325 से अधिक उड़ानों का संचालन करती है।

गोएयर ने एक बयान में कहा, 'पिछले चार सप्ताह के दौरान बिना किसी योजना के हमें अपने विमान खड़े करने पड़ गए जो हमारे मौजूदा परिचालन बेड़े में शामिल थे। अब हमें अपने कारोबार साझेदार एयरबस और प्रैट ऐंड व्हिटनी द्वारा बताया गया है कि वे पिछले वादों के मुताबिक विमानों और 9 मार्च तक नए इंजन की आपूर्ति करने में असमर्थ हैं जो हमारी मौजूदा वृद्धि को रफ्तार देने के लिए आवश्यक है।'

गोएयर के बेड़े में 56 ए320 विमान मौजूद हैं जिसमें 40 ए320 नियो विमान हैं। तीन हजार से अधिक घंटे उड़ान भर चुके विमानों के इंजन की जांच संबंधी नियामकीय निर्देश के बाद उसके सात विमान खड़े हैं। पिछले साल दिसंबर में जांच का यह आदेश जारी किया गया था। सूत्रों ने बताया कि जांच के बाद दिसंबर और जनवरी में इंजन हटा दिए गए थे लेकिन अतिरिक्त इंजन तत्काल उपलब्ध न होने के कारण उन विमानों का परिचालन नहीं हो रहा है।

गोएयर ने कहा, 'हमारे लिए ग्राहकों की सुविधा सर्वोपरि है और इसलिए हमने हर संभव काफी समय पहले इन उड़ानों को रद्द करने की कोशिश की है ताकि हमारे ग्राहकों को अधिक असुविधा न होने पाए। हम उम्मीद करते हैं कि एयरबस और प्रैट ऐंड व्हिटनी की मदद से इन उड़ानों को जल्द से जल्द सुचारू किया जाएगा।'

एयरबस ने एक बयान में कहा है, 'गोएयर एयरबस का एक मूल्यवान ग्राहक है और हमें अपने संबंधों पर गर्व है। एयरबस समय पर इंजन की डिलिवरी सुनिश्चित करने और गोएयर के परिचालन को निर्बाध करने में मदद कर रही है।'

तेल व गैस क्षेत्र से टाटा प्रोजेक्ट्स को बड़े ऑर्डर

बीएस संवाददाता
मुंबई, 23 जनवरी

टाटा प्रोजेक्ट्स को तेल क्षेत्र की दो सरकारी कंपनियों से 6,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इस ऑर्डर में एथनॉल परियोजना और आगामी रिफाइनिंग परियोजना से संबंधित काम शामिल है।

कंपनी को तेल व गैस रिफाइनरी क्षेत्र से कई बड़े ऑर्डर हासिल हुए हैं, जिसकी कुल वैल्यू 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। इनमें से तीन ऑर्डर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी से मिले हैं जबकि एक ऑर्डर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से। कंपनी ने एक बयान में यह जानकारी दी।

टाटा प्रोजेक्ट्स बीपीसीएल के लिए ओडिशा में 2जी बायो एथनॉल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस संयंत्र की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 100 किलोलीटर रोजाना है। कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी की आगामी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स (राजस्थान) पर भी काम कर रही है। टाटा प्रोजेक्ट्स को क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट व वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के लिए भी काम मिला है। *बीएस*

एचडीएफसी लाइफ का कर पूर्व लाभ बढ़ा

बीएस संवाददाता
मुंबई, 23 जनवरी

निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी एचडीएफसी लाइफ का कर पूर्व लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 2.77 फीसदी बढ़कर 263.61 करोड़ रुपये हो गया जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 256.48 करोड़ रुपये रहा था। तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ एकल आधार पर 1.88 फीसदी बढ़कर 250.24 करोड़ रुपये हो गया जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 245.63 करोड़ रुपये रहा था।

तिमाही के दौरान कंपनी की शुद्ध प्रीमियम आय 13 फीसदी बढ़कर 7,854.30 करोड़ रुपये हो गया जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 6,897.68 करोड़ रुपये रहा था। इस दौरान पहले साल का प्रीमियम 23 फीसदी बढ़कर 1,542.96 करोड़ रुपये हो गया जो पिछले साल की समान अवधि में 1,252.34 करोड़ रुपये रहा था।

दिसंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने की अवधि में नए कारोबार का प्रीमियम 22 फीसदी बढ़कर 12,150 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले वित्त वर्ष के पहले नौ महीने के दौरान यह आंकड़ा 9,940 करोड़ रुपये रहा था।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर आज 0.49 फीसदी की बढ़त के साथ 615.75 रुपये पर बंद हुआ।

एफपीआई के अल्पावधि निवेश की सीमा बढ़ी, वीआरआर सीमा दोगुनी

अनूप रॉय
मुंबई, 23 जनवरी

जब विदेशी निवेशक भारतीय ऋणपत्रों की बिकवाली कर रहे हैं पर इक्विटी में निवेश बनाए रख रहे हैं, तब भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को ऐसे निवेशकों के लिए अल्पावधि के निवेश की सीमा बढ़ा दी। साथ ही अगर वे स्वेच्छा से निवेश की योजना पहले घोषित करते हैं तो उनके निवेश की पात्रता दोगुनी कर दी।

दो अलग-अलग अधिसूचना के जरिए केंद्रीय बैंक ने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अब अपने पोर्टफोलियो का 30 फीसदी केंद्र व राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (ट्रेजरी बिल समेत) में कर सकेंगे, जो पहले 20 फीसदी थी। इसी तरह कॉरपोरेट बॉन्ड में भी अल्पावधि निवेश की सीमा अब पोर्टफोलियो के 30 फीसदी के बराबर होगी, जो पहले 20 फीसदी थी।

अल्पावधि की निवेश सीमा में इजाफे के लिए एफपीआई लंबे समय से लॉबीइंग करते रहे हैं। तीन साल में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों में निवेश का लॉक होना अल्पावधि में रिटर्न की इच्छा रखने वाले निवेशकों के हित में है, जो प्रतिफल पर नजर रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि निवेश की अवधि में मुद्रा स्थिर रहे। निवेशक इस अवधि में न सिर्फ मुद्रा का जोखिम लेते हैं बल्कि बढ़ते प्रतिफल की संभावना का भी सामना करते हैं। चूंकि अब आरबीआई की तरफ से दरों में कटौती का चक्र समाप्त होने को है, ऐसे में प्रतिफल में इजाफे की संभावना है। जब प्रतिफल बढ़ता है तो बॉन्ड की कीमतें घटती हैं और निवेशकों के पोर्टफोलियो को नुकसान होता है।

इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने विदेशी निवेशकों को संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) व दिवालिया समाधान का सामना कर रही कंपनियों की तरफ से जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया है। इन प्रतिभूतियों को अल्पावधि की निवेश सीमा से छूट मिलेगी। पहले सिर्फ सिक्योरिटी रिसीट्स को ऐसी छूट मिलती थी।

दूसरे शब्दों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अब कॉरपोरेट बॉन्ड, एआरसी की तरफ से जारी ऋण प्रतिभूतियों और दिवालिया समाधान का सामना कर रही फर्मों की तरफ से जारी बॉन्डों में निवेश की तय सीमा में अपनी इच्छा के मुताबिक निवेश कर सकेंगे, चाहे उनकी परिपक्वता अवधि कुछ भी हो।

इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने वॉलंटरी रिटेंशन रूट (वीआरआर) के जरिए निवेश की सीमा 75,000 करोड़ रुपये के मुकाबले दोगुनी कर 1.50 लाख करोड़ रुपये कर दी है।

आरबीआई ने कहा, एफपीआई को ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश की अनुमति दी गई है, जो सिर्फ ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। हालांकि बॉन्ड डीलरों ने कहा कि निवेश सीमा में इजाफे से निवेश को तत्काल बनाए रखने में मदद नहीं मिलेगी क्योंकि कुल निवेश सीमा का 30 फीसदी सरकारी प्रतिभूतियों में और करीब 45 फीसदी कॉरपोरेट बॉन्ड में करने की सीमा का इस्तेमाल विदेशी निवेशकों ने नहीं किया है।

बॉन्ड बाजार पर नजर रखने वाले एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, इससे बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। जनवरी में अब तक एफपीआई सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का 1.6 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। इससे पहले वे नवंबर व दिसंबर में 1.2 अरब डॉलर की बिकवाली कर चुके हैं। निवेशक अब बजट के आंकड़ों पर स्पष्टता चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आरबीआई प्रतिफल को कितना सहारा दे सकता है, जो लगातार बढ़ रहा है।

गुरुवार को आरबीआई ने ओएमओ के तहत 10,000 करोड़ रुपये के मध्यम व लंबी अवधि के बॉन्ड खरीदे जबकि 2,950 करोड़ रुपये के अल्पावधि वाले बॉन्डों की बिकवाली की जबकि 10,000 करोड़ रुपये की बिकवाली की योजना थी। इसके लिए आरबीआई को हालांकि 35,375 करोड़ रुपये की बोली मिली थी।

रिजर्व बैंक ने किया बदलाव

- अल्पावधि निवेश की सीमा पोर्टफोलियो के 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी की गई
- वीआरआर के तहत निवेश दोगुना कर 1.5 लाख करोड़ रुपये किया गया
- एआरसी, दिवालिया समाधान के दायरे वाली कंपनियों की तरफ से जारी ऋण प्रतिभूतियों को अल्पावधि वाली सीमा से छूट दी गई है
- आरबीआई ने ओएमओ में करीब 3,000 करोड़ रुपये के अल्पावधि बॉन्डों की बिकवाली की

कार्यालय परिसंपत्ति विकसित करने पर 13,000 करोड़ रु. निवेश करेगी डीएलएफ

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 23 जनवरी

रियल एस्टेट डेवलपर डीएलएफ अगले 6-7 साल में करीब 2 करोड़ वर्गफुट ऑफिस स्पेस विकसित करने की योजना बना रही है, जिस पर करीब 13,000 करोड़ रुपये निवेश होगा। इसका करीब 90 फीसदी गुरुग्राम और चेन्नई में होगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलनिस्वामी ने डीएलएफ के नए आईटी/आईटीईएस 'डीएलएफ डाउनटाउन' की आधारशिला रखी, जिस पर अगले छह साल में करीब 5,000 करोड़ रुपये निवेश होंगे।

डीएलएफ के मुख्य कार्याधिकारी मोहित गुजराल ने कहा कि प्रस्तावित 2 करोड़ वर्गफुट में से करीब 1.1 करोड़ वर्गफुट गुरुग्राम में होंगे जबकि करीब 70 लाख वर्गफुट चेन्नई में। इन परियोजनाओं पर क्रमशः 7,500-8,000 करोड़ रुपये और 5,000 करोड़ रुपये निवेश होगा। बाकी देश के अन्य इलाकों में विकसित किया जाएगा।

डीएलएफ का करीब 3.2 करोड़ वर्गफुट वाणिज्यिक/आईटी/आईटीईएस वर्कस्पेस दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और चंडीगढ़ में फैला हुआ है। तारामणि में नई परियोजना के साथ चेन्नई अब गुरुग्राम के बाद डीएलएफ का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कंपनी ने करीब 10 साल पहले तमिलनाडु सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन जमीन आवंटन समेत कई अन्य वजहों से यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पाई। यहां तक कि कंपनी अदालत भी चली गई, लेकिन बाद में याचिका वापस ले ली और अब इस परियोजना की आधारशिला रखी गई है, जिसे विभिन्न चरणों में विकसित किया जाएगा।

डीएलएफ रिटेल बिजनेस के प्रबंध निदेशक श्रीराम खट्टर ने कहा, पहले चरण में 25 लाख वर्गफुट विकसित करने पर कंपनी करीब 1,200-1,500 करोड़ रुपये निवेश करेगी और कंपनी को उम्मीद है कि बाकी चरण छह साल की समयसीमा से पहले पूरा हो जाएगा।

राजस्व सृजन पर टिप्पणी करते हुए खट्टर ने कहा, चेन्नई के पास मनपक्कम में डीएलएफ साइबर सिटी करीब 70 लाख वर्गफुट में फैला हुआ है और यह सालाना करीब 550 करोड़ रुपये किराया राजस्व अर्जित कर रहा है, ऐसे में यह बेंचमार्क हो सकता है।

डीएलएफ ने मनपक्कम में करीब 4,000 करोड़ रुपये निवेश किया है (जमीन को छोड़कर), जिसने 15 साल पहले हुई शुरुआत से अब तक संचयी रूप से 66,000 करोड़ रुपये निर्यात राजस्व का योगदान किया है।

आधार-पैन नहीं तो कटेगा 20 फीसदी टीडीएस

पृष्ठ 1 का शेष

मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान कर विभाग लगातार टीडीएस डिफॉल्ट, भुगतान में देरी, निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अनुपालन नहीं किए जाने से जुड़े मामले उठाता रहा है।

उसने कर चोरी करने वालों का पता लगाने के लिए हर आकलन अधिकारी से 30 करदाताओं के आंकड़े खंगालने को कहा है।

आयकर विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हाल के दिनों में कई जटिल मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए टीडीएस से जुड़े नियमों को कारगर बनाने की जरूरत है। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर आप चालान, टीडीएस प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेजों में कर कटौती और संग्रह की गई राशि की जानकारी देने में नाकाम रहते हैं तो आपको 10 हजार रुपये जुर्माना देना होता है।

बजट में असल समस्याओं पर हो ध्यान

अर्चिस मोहन
नई दिल्ली, 23 जनवरी

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सुझाव दिया है कि केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे और महंगाई दर जैसे वृहद आर्थिक मानकों से हटकर अर्थव्यवस्था की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी व्यय को बढ़ाकर, बुनियादी ढांचे के सृजन के माध्यम से उपभोक्ता मांग में कमी जैसी असली समस्याओं का समाधान करने की जरूरत है।

भाजपा ने सुझाव दिया है कि सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर, सरकारी संपत्तियों के मुद्रीकरण और प्राथमिक व द्वितीयक बॉन्ड बाजारों की स्थिति में सुधार करके राजस्व की कमी के मसले का समाधान किया जा सकता है।

पार्टी के आर्थिक मामलों के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने कहा, 'भाजपा ने पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और महासचिव (संगठन) बीएल संतोष के नेतृत्व में 2 महीने तक चली कवायद के बाद विभिन्न हिस्सेदारों से फीडबैक हासिल किया है, जिनमें 250 संगठन और दर्जनों विशेषज्ञ शामिल हैं।'

भाजपा के नेता बैजयंत जय पांडा और अग्रवाल ने बुधवार को वित्त मंत्री से मुलाकात की और बजट के लिए पार्टी की ओर से सिफारिशें पेश कीं। वित्त मंत्री को भाजपा की ओर से यह दूसरी प्रस्तुति थी। सीतारमण ने इसके पहले भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में 9 जनवरी को पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी।

दिलचस्प है कि भाजपा ने जिन हिस्सेदारों से बात की, किसी ने भी प्रत्यक्ष आयकर में कमी किए जाने की मांग नहीं की। पार्टी ने अपनी ओर से भी प्रत्यक्ष आयकर में किसी तरह की राहत की मांग नहीं की है। सूत्रों ने कहा कि सरकार इस समय संसाधनों की कमी से जूझ रही है और पिछले 5 साल में बहुत कुछ किया गया है, लेकिन इसका असर कुछ सीमित लोगों पर पड़ा है।

ऐसा पाया गया है कि राजकोषीय लक्ष्य हासिल करने पर बहुत ज्यादा जोर दिए जाने व महंगाई पर काबू पाने की पिछले 5 साल की कवायदों ने आर्थिक मंदी में अहम भूमिका निभाई है। इसमें कहा गया है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र इस समय दो तरह के जोखिमों से जूझ रहा है, जिसमें बैंकों से आपूर्ति क्रेडिट और पूंजी सृजन की समस्या शामिल है।

पार्टी की सिफारिशों में कहा गया है कि मंदी की समस्याओं का समाधान उपभोक्ता मांग बढ़ाकर किया जा सकता है। पार्टी ने कहा है कि सरकार को एनबीएफसी पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पूंजी सृजन की बाधाओं को दूर किया जा सके और जहां सार्वजनिक धन नहीं लगा है, एनबीएफसी प्रमोटरों व मित्रों द्वारा समर्थित हैं, वहां कड़ी निगरानी रखे जाने की जरूरत है।

पार्टी के सूत्रों ने कहा कि भाजपा अपने अंत्योदय या समावेशी विकास के दर्शन को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन वह बाजार के प्रति मित्रवत चेहरा होना चाहिए। ज्यादा पारदर्शी बाजारों के लिए लाभांश वितरण कर (डीडीटी), जिंस लेनदेन कर (सीटीटी) और प्रतिभूति लेन देन कर (एसटीटी) से दूर रहने की सिफारिश की गई है। सीटीटी या एटीटी से बहुत ज्यादा राजस्व नहीं आता है, लेकिन वित्तीय बाजारों पर इसका बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से लेन देन की लागत बढ़ने पर कारोबार सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग जाता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के लिए इसमें कहा गया है चल रही योजनाओं पीएम किसान, मनरेगा और आयुष्मान का बजट आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए।

अपने फीडबैक में पार्टी ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रत्यक्ष नकदी अंतरण से किसानों को मदद मिली है और इसका विस्तार किया जाना चाहिए जिससे कि बिचौलियों या आढ़तियों को दूर किया जा सके।

पार्टी ने खाद्य प्रसंस्करण की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने की भी सिफारिश की है, जिस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। साथ ही कोऑपरेटिव को भी छूट और लाभ उसी तरह से मिलना चाहिए, जैसा सरकार की ओर से कॉर्पोरेट्स को मिल रहा है।

वित्त मंत्री को बजट पूर्व सुझाव

- वृहद आर्थिक मानकों और महंगाई दर की जगह खपत बढ़ाने पर हो ध्यान
- 5 साल तक महंगाई व राजकोषीय घाटे पर जोर ने मंदी में निभाई अहम भूमिका
- भाजपा बाजार के प्रति मित्रवत रहकर समावेशी विकास की अपनी पुरानी नीति पर कायम

गैस इन्फ्रा में आएंगे 4 लाख करोड़

एजेंसियां
नई दिल्ली, 23 जनवरी

तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि भारत ने 2030 तक ऊर्जा बॉस्केट में पर्यावरण अनुकूल ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है, जिससे देश में गैस आपूर्ति व वितरण संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास में अगले 5 साल में 4 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा।

उन्होंने कहा कि चालू या हाजिर बाजार में गिरती दरों को देखते हुए भारत कतर के साथ दीर्घावधि एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट के मूल्य पर नए सिरे से बातचीत की मांग कर सकता है। प्रधान ने कहा, 'कतर के ऊर्जा मंत्री इस महीने के अंत में द्विपक्षीय बातचीत के लिए भारत आ रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे।'

दूरसंचार विभाग की ओर से करीब 3 लाख करोड़ रुपये के बकाये की मांग पर प्रधान ने कहा कि गैर दूरसंचार पीएसयू जैसे गेल, ऑयल इंडिया और पॉवर ग्रिड से की गई यह मांग 'संचार की कमी' की वजह से है, इन फर्मों का इस तरह का कोई बकाया नहीं है। उच्चतम न्यायालय के 24 अक्टूबर के फैसले को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने गेल इंडिया से 1.72 लाख करोड़ रुपये, ओआईएल से 48,000 करोड़ रुपये और पावर ग्रिड से 40,000 करोड़ रुपये की व रेलटेल और अन्य सरकारी उपक्रमों से भी की गई है।

ओएनजीसी को मिलीं 28 बोलियां

सरकारी कंपनी ओएनजीसी को उसके 64 छोटे व सीमांत गैस क्षेत्रों के 50 क्षेत्रों के लिए बोलियां मिली हैं। यह अपने तरह की पहली बोली है, जिसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों को शामिल किया जा रहा है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 17 जनवरी को बंद हो रही इस बोली में 50 क्षेत्रों के लिए 12 कंपनियों ने 28 बोलियां लगाई हैं।

धन मिलने के बाद वैश्विक विस्तार की राह पर बाउंस

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 23 जनवरी

- स्कूटर शेयरिंग स्टार्टअप बाउंस दुनिया के दूसरे देशों में देगी दस्तक
- फर्म ने 10.5 करोड़ डॉलर जुटाए हैं जिससे कंपनी का मूल्य 50 करोड़ डॉलर के करीब हो गया है

बाइक और स्कूटर शेयरिंग स्टार्टअप बाउंस अब अपना विस्तार दुनिया के दूसरे देशों में भी करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही वह देश के सभी बड़े शहरों और 100 नए शहरों विशेषकर महानगरों एवं छोटे शहरों में भी अपना परिचालन बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी ने हाल ही में 10.5 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। कंपनी को मध्यम और छोटे शहरों में अपने कारोबार के लिए काफी संभावना नजर आ रही है।

बाउंस के मुख्य परिचालन अधिकारी और सह संस्थापक अनिल जी ने कहा, 'हमने सफलतापूर्वक यह साबित किया है कि यह सेवा एक बड़ी आबादी को आकर्षित करती है। आगामी तिमाहियों हमारी कोशिश 10-12 बड़े शहरों और अपेक्षाकृत 100 छोटे शहरों में अपनी सेवा का विस्तार करने की होगी।' उन्होंने कहा, 'हम मानते हैं कि छोटे शहरों में बड़े मौके मौजूद हैं क्योंकि वहां बड़े शहरों की तर्ज पर परिवहन की सभी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।'

फिलहाल बाउंस बेंगलूरु और हैदराबाद के साथ साथ मैंगलोर और विजयवाड़ा सहित छह छोटे शहरों में सेवा दे रही है। अब इसकी योजना महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में पांव जमाने की है। वैश्विक स्तर पर देखें तो इस कंपनी की प्रतिस्पर्धा लाइम और बर्ड जैसी स्कूटर रेंटल कंपनियों से है। बाउंस अगले कुछ वर्षों में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में उतरने की भी योजना बना रही है।

अनिल ने कहा, 'हम मानते हैं कि बाउंस जैसी सुविधा प्रदान कर रही है उसकी मौजूदगी दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में भी कराई जा सकती है। बहरहाल, हमारा मुख्य ध्यान भारत पर बना रहेगा। इसके साथ ही हम निश्चित तौर पर भारत से बाहर यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के शहरों में भी अपनी सेवा की मौजूदगी की संभावना देख रहे हैं।'

फर्म ने कहा कि एस्सेल की अगुआई में सीरीज डी फंडिंग के जरिये 10.5 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। मौजूदा निवेशकों के साथ ही एस्सेल पार्टनर्स इंडिया, चिराटे वेंचर्स, फाल्कन एज, मावरिक वेंचर्स, ओमिड्यार नेटवर्क इंडिया, क्वॉलकॉम वेंचर्स और सिक्वोया कैपिटल इंडिया ने भी भागीदारी की।

पुरी का उत्तराधिकारी तलाशेगी जेंडर

रॉयटर्स
मुंबई, 23 जनवरी

भारत में निजी क्षेत्र के शीर्ष बैंक एचडीएफसी बैंक ने प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी की तलाश के लिए वैश्विक एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म इगॉन जेंडर को नियुक्त किया है। एचडीएफसी बैंक के प्रवक्ता नीरज झा ने कहा, 'तलाश समिति ने इगॉन जेंडर की सिफारिश की है और उसे बैंक के बोर्ड ने एकमत से नियुक्त किया है।'

इस मामले से जुड़े 4 सूत्रों ने कहा कि पिछले साल नवंबर में नियुक्त 6 सदस्यों वाली आंतरिक तलाश समिति पुरी के उत्तराधिकारी के चयन में आम सहमति पर नहीं पहुंच सकी, जो 1994 में बैंक के आने के बाद से ही देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक से जुड़े हुए हैं। पुरी का कार्यकाल इस साल अक्टूबर में खत्म हो रहा है। वह तलाश समिति के सलाहकार भी हैं, जिसे उचित अभ्यर्थी चिह्नित करने का काम सौंपा गया है।

नियमों के मुताबिक बैंक को किसी नई नियुक्ति की पुष्टि करने के पहले भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी लेना होगा।

सूत्रों के मुताबिक पुरी और हाउसिंग फाइनैंस कंपनी एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख के बीच अपनी पसंद के उत्तराधिकारी को लेकर खींचतान है।

तीन सूत्रों ने कहा कि पुरी के चयन में एचडीएफसी के कार्यकारी निदेशक भावेश झवेरी, शशिधर जगदीशन और कैजाद भरूचा शामिल हैं। दो सूत्रों ने कहा कि पारेख, परेश सुखतनकर को स्थापित करने की कवायद कर रहे हैं, जिन्होंने पुरी के डिप्टी के रूप में 2018 में इस्तीफा दिया था।

'परियोजनाओं में देरी स्वीकार्य नहीं, समयसीमा का करें पालन'

भाषा
नई दिल्ली, 23 जनवरी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि राजमार्ग परियोजनाओं को तैयार करने में देरी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण कंपनियों से परियोजना क्रियान्वयन की समयसीमा का कड़ाई से पालन करने को कहा।

गडकरी ने ऑनलाइन पोर्टल गति की भी शुरुआत की। यह प्रगति पोर्टल की तरह है जिसका उपयोग प्रधानमंत्री कार्यालय परियोजनाओं की निगरानी के लिए करता है। उन्होंने तीन लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजनाओं में देरी स्वीकार्य नहीं है। परियोजना का कार्यक्रम के अनुसार कड़ाई से पालन किया जाए।

गडकरी ने कहा कि कोई भी अंतर-मंत्रालयी मुद्दा आता है तो उसे मंत्रालय के नोटिस में लाया जाए ताकि उसके समाधान में तेजी लाई जा सके। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुदुच्चेरी, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों की परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

बीएस सूडोकू 3647

							2	5
3			2	5		1		
		4		7			3	
					9		8	7
		1				6		
4	8		3					
	4			2		8		
		5		1	8			3
2	7							

परिणाम संख्या 3646

7	1	5	3	6	4	8	2	9
9	3	4	1	8	2	5	6	7
6	8	2	7	5	9	1	3	4
4	6	7	2	3	8	9	5	1
8	9	1	6	4	5	2	7	3
5	2	3	9	7	1	6	4	8
1	7	6	8	2	3	4	9	5
2	5	9	4	1	7	3	8	6
3	4	8	5	9	6	7	1	2

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान ★★☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2025/2030, जौ 1760/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4300/4350, तिल सफेद 8900/9100, सोया (टीन) 1550/1600, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1475/1575,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2000/2010, गेहूं शरबती 2900/3000, चावल शरबती सेला 3750/3800, स्टीम 4300/4400, लालमती 3300/3350, चावल (सोना) 2900/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1395, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1472, फ्लैक 1410, डीएमओ 990, टरपीन लैस बोल्ड 1495

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1180/1250, खुरपा 1050/1100,चाकू 1040/1150, रसकट 950/935, शक्कर 1200/1220, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3310, सिहोरा 3300, बुंदकी 3260, बुढ़ाना 3320,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1100/1130, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4300, खल: सरसों 2100/2150, बिनौला 2350/2450, चना छिलका 2150/2200,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5500/5600, गेहूं (मिल) 2100/2110, मक्की 2125/2130, बाजरा 1850/1860, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3800/3825, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4440/4450,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2050/2100, ग्वार 3800/3850, जौ 2130/2140, सरसों लूज 4000/4050

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4500/4600, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4000/4050, ग्वारगम 7300/7400, बाजरा (गुजरात) 1840/1850, बाजरा (जयपुर) 1850/1860, चना 4100/4200, काबली चना

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)126, राइसब्रान (अखाद्य) 123, खल सरसों 1960, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1200, लाल 1200, कंटीन्यूअस 1280,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7800/8500, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7400/8400, उड़द धोया 9000/9900, छिलका 8700/9400, दाल मसूर 5900/6200, चनादाल 5400/5500,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 5900/6000, सेला 5400/5425, शरबती साधारण सेला 3700/3750, शरबती स्टीम 4100/4150,चावल 1509 सेला 5050/5100, धान: शरबती 2050/2100,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4100/4160, हरियाणा 4080/4100, राजस्थान 4050/4120, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2400/2500, सरसों खल 2080/2100,

फाजिल्का
गेहूं 2090/2100, सरसों 4250/4325 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4100/4110, कपास देशी 5100/5200, कपास नरमा (क्विं.) 5200/5300, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2400/2500,

जालंधर
गेहूं दड़ा 1985/2040, चावल परमल कच्चा 2375/2425, से ला 2300/2350, मक्की यूपी 2140/2150, दाल उड़द छिलका 8800/10000, चना देशी 4700/4800, दाल चना 5100/5200, काबली चना 5200/6100, राजमां चित्रा पुणे 7200/8600,चीन 8000/8500,

करनाल
गेहूं दड़ा 2000/2025, बासमती चावल 6400/6500, धान 1121 नं. 2900/2950, पूसा 1509 धान 2850/2875, शरबती धान 2100/2150, सेला (1509 नं.) चावल 5050/5100, स्टीम 6000/6100,

हिसार
ग्वार 3800/3850, जौ 1840/1850, सरसों 4000/4050, मूंग 6900/7000, गेहूं 2080/2100,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2150/2180, आटा (प्रति 44 किलो) 1040/1060, मैदा 1160/1180, देशी घी (एक ली/जार) 380/500, रिफाइंड (टीन) 1500/1550,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4050/4100, खल बिनौला मोटी 2300/2400, बिनौला 2700/3200, सरसों तेल 9050/9100, गेहूं 2150/2175, ग्वार 3850/3900, बाजरा 1850/1900 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 291

संविधान सर्वोपरि

सन 1950 में 26 जनवरी को भारत को अपना संविधान मिला जो विश्व के सर्वाधिक संपूर्ण, आधुनिक और उदार संविधानों में से एक है। सत्तर वर्ष बाद देश को न केवल उस स्मृति का जश्न मनाना चाहिए बल्कि स्वयं को एक बार फिर संविधान के सिद्धांतों के प्रति शाब्दिक और भावनात्मक स्तर पर समर्पित करना चाहिए। एक राष्ट्र राज्य के रूप में भारत का अस्तित्व, एक देश के रूप में उसका विकास और गत सात दशक में एक अर्थव्यवस्था के रूप में उसकी प्रगति में यह तथ्य भी शामिल है कि देश का संविधान व्यापक विवेचना से उभरा और इसकी संस्थापक पीढ़ी ने संविधान के तौर तरीकों और सिद्धांतों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता दिखाई।

इसमें बहुत कम संदेह है कि बीते सात दशक में ऐसे भी अवसर आए जब देश की उदारवादी बुनियाद पर हमले हुए। आपातकाल की घोषणा ऐसा ही एक अवसर था। इस बात को लेकर चिंतित होने की पर्याप्त वजह है कि भारत एक बार फिर वैसे ही दौर से गुजर रहा है। भले ही यह सन 1970 के दशक की तरह स्पष्ट नहीं है। द इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) हर वर्ष लोकतंत्र सूचकांक जारी करती है। यह सूचकांक दर्शाता है कि विभिन्न देश लोकतांत्रिक संस्थानों और उनसे जुड़े अनुभव के मामले में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत एक वर्ष में 10 स्थान नीचे लुढ़क गया और वर्ष 2018 के 41वें स्थान से 2019 में 51वें स्थान पर आ गया। ईआईयू ने कहा कि देश के इस सूचकांक में पिछड़ने की प्रमुख वजह यहां नागरिकों को मिलने वाली आजादी में आई कमी है। उसने असम में राष्ट्रीय नागरिक न पंजी लागू करने, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता और पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने और नए नागरिकता संशोधन अधिनियम को इसका कारण बताया।

हालांकि ऐसे सूचकांकों पर 100 प्रतिशत यकीन नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इस सूचकांक में भारत की स्थिति में गिरावट व्यापक साझा चिंताओं को प्रदर्शित करती है। इस बात की जांच करने का वक्त आ गया है कि देश के मूल संवैधानिक सिद्धांतों को कैसे एक बार पुन: उनकी जगह दिलाई जा सकती है। तमाम मोर्चों पर हम संविधान के लिखे और उसकी आत्मा में निहित धारणाओं का पालन करने में नाकाम रहे हैं। यह न केवल धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्य को चुनौती है बल्कि ऐसे सवाल भी हैं कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार सुरक्षित रहेंगे और एक नए युग में उनका उन्नयन होगा या नहीं। कोई संविधान स्थिर नहीं होता और वह समय के साथ बदलता है लेकिन भारतीय संविधान की उदार बुनियाद बनी रहनी चाहिए। जिन संस्थानों पर इस बुनियाद को बचाने का दायित्व है उन्हें अपनी स्वायत्तता को लेकर सचेत रहना चाहिए और बुनियादी संवैधानिक सिद्धांतों के बचाव के लिए मुस्तैद रहना चाहिए।

ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकतंत्र में जहां राजनीतिक बदलाव और नए विचारों का आदर होना चाहिए, वहीं उसे संवैधानिक सिद्धांतों को चुनौती नहीं देनी चाहिए। ऐसे सिद्धांतों के बल पर ही किसी राज्य में निरंतरता आती है। यह न केवल लोगों को अवसर उपलब्ध कराता है बल्कि ऐसी सुरक्षा भी देता है जिसके बिना निवेश और वृद्धि असंभव है। हां, बदलाव होना चाहिए: निजता का मान रखा जाना चाहिए, अभिव्यक्ति पर उपनिवेशकालीन प्रतिबंध और सुरक्षा बलों की अत्यधिक शक्तियां समाप्त होनी चाहिए और संपत्ति के अधिकारों की समीक्षा होनी चाहिए। परंतु यह सब उस संविधान के दायरे में रहकर हो सकता है जो सात दशक पहले लिखा गया और जिस पर उस दौर में पूरी बहस हुई और बाद में भी होती रही। राजनीतिक वर्ग संविधान को लेकर जुबानी जमाखर्च से काम चलाता रहा है, जबकि उसे हकीकत में उसका पालन करना चाहिए।

अजय मोहंती

आम बजट से क्या है निवेशकों की उम्मीद

आगामी बजट में इस बात की असली परीक्षा होगी कि केंद्र सरकार सुधारों को लेकर किस कदर गंभीर है। इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं **आकाश प्रकाश**

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संभवत: इस सरकार का अब तक का सबसे महत्त्वपूर्ण बजट पेश करेंगी। निवेशक बहुत बारीकी से बजट भाषण और बजट दस्तावेज को देखेंगे कि क्या मंदी से निपटने और उससे आगे की राह का कोई संकेत मिलता है। निवेशक एक सुसंगत आर्थिक योजना देखने को उत्सुक हैं।

वैश्विक निवेशक इस बात पर सहमत हैं कि कारोबारी माहौल में सुधार के गंभीर प्रयास का वक्त आ गया है। अगर अभी बड़े सुधार के प्रयास नहीं दिखे तो आर्थिक कमजोरी के कारण भारी बहुमत होते हुए भी भविष्य में कुछ महत्त्वपूर्ण नहीं हो पाएगा।

कुछ बातें स्पष्ट हैं। राजकोषीय फिसलन काफी होगी। अधिकांश निवेशकों को उम्मीद है कि राजकोषीय फिसलन 3.3 फीसदी के तय लक्ष्य की जगह जीडीपी के 3.7 से 3.8 फीसदी तक रहेगी। कम नॉमिनल जीडीपी के कारण 11 आधार अंकों की कमी आई और यह 3.3 फीसदी से बढ़कर 3.41 फीसदी हुआ। हालात को देखते हुए इस पर 30 से 40 आधार अंकों की फिसलन सहज स्वीकार्य होगी।

निवेशक चाहेंगे कि इस राजकोषीय गुंजाइश का इस्तेमाल पूंजीगत व्यय के लिए हो। हालांकि उन्हें उम्मीद होगी कि आगे चलकर यह पटरी पर आ जाएगा और वे 2021 के लिए 3.3 से 3.5 फीसदी के लक्ष्य की अपेक्षा करेंगे। निकट भविष्य में किसी को इसके 3 फीसदी रहने की उम्मीद नहीं है।

राजकोषीय मोर्चे पर सीमित गुंजाइश और मौद्रिक नीति की बाधाओं को देखते हुए अब वास्तविक सुधारों का वक्त आ गया है। वित्त मंत्री अगर क्षेत्रवार तरीके से आगे बढ़ें और निवेश और निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव करें तो बेहतर होगा।

वैश्विक निवेशकों के लिए इक्विटी पर दीर्घावधि का पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर एक अहम बात हो सकता है। एलटीसीजी से ज्यादा राजस्व नहीं मिला है और प्रशासनिक रूप से इसने वैश्विक फंडों के लिए कठिनाई पैदा की है। लंबी अवधि के कई निवेशक (एंडोवमेंट, सॉवरिन वेल्थ और फाउंडेशन) अपने गृह क्षेत्र में कोई कर नहीं चुकाते और भारत में कर चुकाना उन्हें अलग-थलग करना लगता है।

पूंजीगत लाभ कर को पूरी तरह खत्म करना व्यवहार्य नहीं होगा लेकिन कम से कम दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ को रियायत दी जा सकती है। इससे भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश पर अनुमानित कर पश्चात प्रतिफल बढ़ेगा और कंपनियों के लिए पूंजी की लागत कम होगी। इक्विटी के लिए इसकी भरपाई प्रतिभूति लेनदेन कर में मामूली इजाफा करके की जा सकती है। इससे वैश्विक पूंजी प्रदाताओं में सकारात्मक संदेश जाएगा।

बजट में एक और कदम पुराने वाहनों को खत्म करने की योजना को फंड करने का होना चाहिए। 15 साल से पुराने किसी भी वाणिज्यिक वाहन को कबाड़ में बेचने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इससे करदाताओं पर 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि वाहन उद्योग को काफी गति मिलेगी। प्रदूषण में काफी कमी आएगी और वाणिज्यिक वाहनों की ईंधन किफायत सुधरेगी। यह सबके लिए लाभप्रद होगा।

वाहन उद्योग बहुत बड़ा रोजगार प्रदाता है और यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। फिलहाल इस उद्योग की हालत खस्ता है और कबाड़ संबंधी योजना इसकी बहुत मदद करेगी। ऐसी योजनाओं को दुनिया भर में सराहना मिलती रही है। खासतौर पर वित्तीय संकट के दौर में ये कारगर साबित हुई हैं। भारत भी इसे अपना सकता है। पैसे की कमी इकलौती बाधा हो सकती है लेकिन इसे अपनाया जाना चाहिए।

स्टार्टअप को लेकर सरकार के रुख पर भी नजर रखनी होगी। हमारे पास स्टार्टअप को लेकर अच्छी योजना और धनराशि है। सरकार ने स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए काफी कुछ किया है। उसने उनकी महत्ता को पहचाना है। उन्हें यह इजाजत होनी चाहिए कि वे 15 वर्ष तक नुकसान वहन कर सकें। फिलहाल यह इजाजत आठ वर्ष तक की है। काफी संभव है कि मुनाफा कमाने के पहले वे लंबे समय तक नुकसान में रहें। अगर उन्हें घाटे को आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाती है तो नकदी प्रवाह और शुद्ध मार्जिन में सुधार होगा। स्टार्टअप को कंपनी अधिनियम की धारा 42 से निजात भी दी जा सकती है। जबकि चुनिंदा परिस्थितियों में इन स्टार्टअप को डीम्ड सरकारी कंपनी भी माना जा सकता है।

बीते कुछ वर्ष के दौरान निर्यात के मोर्चे पर काफी निराशा हाथ लगी है। घरेलू मांग में सुधार के बीच निर्यात वैश्विक मांग से लाभान्वित होने का बेहतर जरिया होगा। इसका असर निवेश पर भी पड़ेगा। व्यापक प्रोत्साहन पैकेज और नीतियां निवेश प्रतिस्पर्धा में सुधार कर सकती हैं।

दूरसंचार और बिजली क्षेत्र की बात करें तो हमें उद्योग आधारित हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। दूरसंचार में सरकार को बीच का रास्ता तलाश करना होगा और उद्योग जगत को इस समायोजित सकल राजस्व की समस्या से निजात दिलानी होगी।

बिजली क्षेत्र में सरकारी बिजली बोर्ड दिवालिया हैं। उदय योजना नाकाम साबित हुई है। कोई भी व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में क्यों निवेश करेगा जहां प्रमुख प्रतिपक्ष ही दिवालिया हो। राज्य बिजली बोर्ड पर निजी बिजली कंपनियों का बकाया बढ़कर 46,000 करोड़ रुपये हो चुका है।

प्रत्यक्ष कर की बात करें तो उम्मीद है कि दरों में कटौती देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ रियायतों को तार्किक बनाने और दरों को आंशिक रूप से संतुलित किए जाने की अपेक्षा की जा सकती है।

विनिवेश के मोर्चे पर 2020 के लक्ष्य हासिल नहीं होंगे लेकिन 2021 में बीपीसीएल, कॉनकॉर और एयर इंडिया की मदद से बेहतर परिणाम मिलेंगे। इसके बाद सरकार को टाटा कम्युनिकेशंस और हिंदुस्तान जिंक तथा अन्य कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचनी चाहिए। इन दोनों कंपनियों के रोजमर्रा के काम में सरकार शामिल ही नहीं है तो हिस्सेदारी रखने का क्या लाभ?

सरकार को अन्य सरकारी उपक्रमों की सूची बनाकर देखना चाहिए कि उनसे कितनी राशि हासिल की जा सकती है। एनएमडीसी इसका स्पष्ट उदाहरण है। हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज लिमिटेड एक और उदाहरण है। उसके पास हजारों करोड़ की जमीन है और इसका मुद्रीकरण होना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम सबसे मूल्यवान सरकारी संपत्ति है। उसने निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को भी बहुत अच्छी तरह संभाला। क्या सरकार एलआईसी को सूची में शामिल करेगी? एलआईसी के मामले में सरकार को नियंत्रण अपने पास रखकर आंशिक हिस्सेदारी बेचनी चाहिए।

बजट में कई अन्य क्षेत्रवार घोषणाएं की जा सकती हैं। अचल संपत्ति और एनबीएफसी पर ध्यान दिया जा सकता है। बजट ऐसा होना चाहिए जो देश की अर्थव्यवस्था में भरोसा बहाल करे और निवेशकों तथा देश के उद्यमी जगत को आश्वस्त करे। उन्हें भरोसा हो जाना चाहिए कि सुधार सरकार की प्राथमिकता में हैं।

क्या भारतीय कंपनियों के बोर्ड वाकई में असरदार हैं?

बाअदब

सोमशेखर सुंदरेशन

अगर भारतीय कारोबारों के लिए वर्ष 2020 में सबसे जरूरी नियामकीय सुधार पर गौर करना है तो वह कंपनियों के निदेशक मंडल की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए एक ढांचा खड़ा करना है। हमें खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या भारतीय कंपनियों के बोर्ड वाकई में असरदार हैं?

नया साल बोर्ड नियमन के क्षेत्र में एक बहाने के साथ शुरू हुआ है। चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) पदों पर एक ही शख्स के बैठने पर रोक लगाने वाले प्रावधान की समयसीमा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दो साल के लिए बढ़ा दी है।

कंपनी बोर्ड के ढांचे की सफाई करने से जुड़ा यह एक और उपाय है। जहां हमारा नियामकीय ढांचा इस बारे में बहुत साफ है कि एक बोर्ड को कैसा दिखना चाहिए और उसमें कौन लोग शामिल होने चाहिए। कंपनी बोर्ड के पर्यवेक्षण एवं संचालन का असर कानून में शायद ही परखा जाता है।

इस दिशा में उठाए जा रहे अधिकांश कदम वे हैं जो एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सक्रिय नियामक उठाते। पिछले दशक में सेबी और कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के बीच जारी नियामकीय जंग का नतीजा परस्पर विरोधाभासी एवं अतिव्यापी प्रावधानों के तौर पर सामने आया है। सूचीबद्धता के नियमों और कंपनी कानून में इन्हें लागू किया गया है। यह प्रारूप मोटे तौर पर बोर्ड संयोजन, स्वतंत्र निदेशकों की अवधारणा, निदेशक बनने की योग्यता और कंपनी संचालन की गुणवत्ता से सीधे तौर पर न जुड़ा होते हुए भी सामाजिक प्रतिनिधित्व को रेखांकित करने वाले बिंदुओं के इर्दगिर्द घूमता है।

कंपनी बोर्ड संचालन के प्रति इस तरह के रवैये का नतीजा बोर्ड संरचना पर बारीक नजर के तौर पर सामने आया है। इसका मतलब है कि बोर्ड की असरकारिता पर समान अहमियत दिए बगैर उसके ढांचे पर जोर होता है। इससे पहले कभी भी कंपनियों के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) का पद इतनी गहन समीक्षा एवं नियामकीय निशाने पर नहीं रहा है। जहां मीडिया की तवज्जो और उसके हिसाब से नियामकीय नजर किसी खास सीईओ पर होती है वहीं समस्या के केंद्र में कंपनी बोर्ड की नाकामी और सामूहिक पर्यवेक्षण एवं निगरानी के एक मंच के तौर पर उसका निष्प्रभावी प्रदर्शन है।

एक व्यक्ति के तौर पर हम भारतीय एक ताकतवर सीईओ से किसी नायक जैसे नेतृत्व को पसंद करते हैं। सीईओ को एक कंपनी के अधिष्ठाता देवता या सीजर की तरह देखा जाता है। जब हालात अच्छे होते हैं तो सीजर को अवतार मान लिया जाता है जबकि हालात खराब होने पर उसे शैतान भी बना दिया जाता है। सीजर पर निगरानी रखने का दायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का होता है जिससे संसद की तरह नियंत्रण एवं संतुलन की अपेक्षा रहती है और उसे समय-समय पर परामर्शदाता की भूमिका भी निभानी होती है। लेकिन एकल नायकों के लिए चाहत रखने वाले हमारे समाज में इस सामूहिक नेतृत्व को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है।

इसी तरह सीईओ का दायित्व निभा रहे प्रबंधकों को भी आत्मपरीक्षण करने की जरूरत है। अमूमन बोर्ड के सदस्य वही होते हैं जिनके साथ सीईओ सहज होते हैं। भारतीय परिवेश में आंशिक स्वामित्व और सीईओ का पद एक व्यक्ति के पास होने के संभावना अधिक होने से यह बात और भी साफ होती है। लेकिन जिस कंपनी में सीईओ की स्वामित्व हिस्सेदारी नहीं होती है वहां भी शेयरधारकों के समक्ष निदेशक पद के लिए उन्हीं उम्मीदवारों के नाम रखे जाते हैं जिनके साथ प्रबंधन सहज महसूस करता है। निदेशक पद के लिए नाम सुझाने का दायित्व कायदे से एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के पास होता है लेकिन उसके सदस्यों में खुद को ही चुनने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है।

असफल या कलंकित होने वाले तमाम सीईओ में एक बात समान है कि वह सीईओ समय के साथ बेहद ताकतवर होते चले गए और निदेशक मंडल उन पर कारगर लगाम एवं निगरानी नहीं रख पाए। फिर भी सीईओ के मुश्किल में फंसने पर निदेशकमंडल के लिए उसके पीछे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब विरोध में खड़ा होने वाला पक्ष नियामक होता है।

सीईओ को जवाबदेह ठहरा पाने में नाकाम बोर्ड अक्सर हमले से घिरे सीईओ के बचाव में भी आगे नहीं आ पाता है। किसी भी सूरत में कंपनी बोर्ड के पास एक प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने वाला ढांचा नहीं होता है जो बेहतर नतीजे दिला सके। असल में, कंपनियों के बोर्ड को पूरी तरह मनमाने और खराब फैसलों की पीड़ा का अहसास ही नहीं है और वो प्रबंधन या मालिक या फिर दोनों को ही अपना समर्थन देकर खुश होते हैं।

दुखद है कि नियामक का रुख निदेशकों के लिए कंपनी संचालन से संबंधित परीक्षा में पास होने की शर्त के तौर पर सामने आ रहा है। हमें आश्वस्त होना चाहिए कि हाल में सीईओ को ठीक से नहीं संभाल पाने वाली हरेक कंपनी का हरेक निदेशक ऐसी परीक्षाएं काफी आसानी से पास कर लेगा।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनियों और उसके गवर्नरों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय का प्रावधान रखा गया था। लेकिन कानून लागू होने के आधे दशक बाद भी यह पूरी तरह नदारद है। इससे भी बुरा यह है कि समाज के भीतर कंपनी कानून के बारे में जानकारी एवं अपेक्षाएं इतनी कम हैं कि तमाम लोग नियंत्रण एवं संतुलन की कड़ी परीक्षा से काफी खुश हैं ताकि जवाबदेही बढ़ाई जा सके। कंपनी बोर्ड की असरकारिता का मसला मुकदमेबाजी एवं संबद्ध न्याय-क्षेत्र से ही हल किया जा सकता है। तब तक हम कानून में फेरबदल कर सकते हैं लेकिन उसके मामूली असर ही होंगे।

(लेखक अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)

कानाफूसी

सिद्धू की वापसी

अपनी जोरदार वाक कला के लिए मशहूर और क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर वापसी करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से सार्वजनिक मंचों से नदारद नजर आ रहे सिद्धू को दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक का दर्जा दिया है। इस सूची में उनका नाम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मनमोहन सिंह जैसे दिग्गजों के साथ शामिल किया गया है। गत वर्ष जुलाई में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मतभेद होने के बाद सिद्धू ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ही वे राजनीतिक गुमनामी से गुजर रहे थे। गत वर्ष हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी उन्हें प्रचार में शामिल नहीं किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ उनकी दोस्ती भी पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गई थी। अमरिंदर सिंह ने शिकायत की थी कि सिद्धू ने पाकिस्तान में खान के शपथग्रहण समारोह में शामिल होने के पहले उनकी इजाजत नहीं ली थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से सिद्धू के गले मिलने की तस्वीरें भी उस वक्त पार्टी के लिए शर्मिंदगी का सबब बनी थीं।

नवजोत सिंह सिद्धू

आपका पक्ष

विरोध प्रदर्शन और जनता का नुकसान

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों ने पिछले एक माह से अधिक समय से सड़क बंद कर रखी है। इस वजह से दिल्ली-नोएडा को जोड़ने वाली कालिंदी कुंज सड़क बंद है। इससे दिल्ली से नोएडा आने में लोगों को अतिरिक्त दो घंटे का समय लग रहा है। वाहनों से बड़ी संख्या के कारण आश्रम और डीएनडी में घंटों जाम लग रहा है। इस वजह से लोगों को तीन घंटे से अधिक समय लग रहा है। एक निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि वह सड़क बंद होने के कारण रोजाना विलंब से कार्यालय पहुंच रहा था। तीन घंटे कार्यालय पहुंचने में और तीन घंटे घर लौटने तथा आठ घंटे की नौकरी से 14 घंटे से अधिक लग रहा था। एक माह में आधा वेतन मिलने और सड़क बंद होने से अधिक किराया लगना उस कर्मचारी की नौकरी छोड़ने की वजह बनी। लोगों ने अदालत से सड़क खाली करने की गुहार लगाई जिसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस को सड़क खाली कराने का आदेश दिया। इसके बावजूद आज तक सड़क खाली नहीं हो सकी। सड़क बंद से आम लोगों को परेशानी के साथ और भी नुकसान हो रहा है। जाम के कारण पेट्रोल-डीजल अधिक खर्च हो रहा है। इसके अधिक जलने से वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। बहरहाल लोगों का विरोध प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन क्या अपने अधिकार के लिए दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन करना उचित है? अत: विरोध प्रदर्शन के लिए एक नियत स्थान होना चाहिए जिससे अन्य लोगों को परेशानी नहीं हो तथा उनके अधिकारों तथा हितों की रक्षा हो सके। इससे देश को होने वाले बेवजह नुकसान से बचाया जा सके।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के विरोध में पिछले एक माह से महिलाएं सड़क पर बैठी हैं

देश में और भी समस्याएं हैं

मोदी सरकार ने अपनी पहली और दूसरी पारी में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए तथा आगे भी शायद और फैसले लें। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, तीन तलाक पर कानून, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधान हटाना, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी जैसे फैसले मोदी सरकार ने किए। लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, उद्योग-धंधे और व्यापार को सुधारने की तरफ कोई खास रुचि नहीं दिखाई। इससे देश में बेरोजगारी के बढ़ने और देश की आर्थिक सुस्ती के निराशाजनक आंकड़े सामने आए। उच्चतम न्यायालय ने सीएए पर रोक लगाने से अभी फिलहाल मना कर दिया है। इस मुद्दे को जितना उछाला जाएगा, यह उतना उलझता जाएगा। देश में पिछले कुछ महीनों से प्याज और अन्य सब्जियों तथा अन्य खाने पीने वस्तुओं की कीमतें आसमान पर हैं। इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना मीडिया की जिम्मेदारी है। एक-दो महीने पहले राजस्थान के एक अस्पताल में सैड़कों बच्चों ने दम तोड़ दिया इस पर भी मीडिया में काफी देर से दिलचस्पी दिखाई।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

रत्न-आभूषण समेत बड़े लेनदेन पर नजर

सरकार बड़े लेनदेन को आधार कार्ड से जोड़ने की कर रही है कोशिश

राजेश भयानी
मुंबई, 23 जनवरी

- आधार से जुड़ने के बाद बगैर पैन नंबर वाले किसानों पर भी रखी जा सकेगी नजर
- आभूषण क्षेत्र को फिर से पीएमएलए के दायरे में लाया जा सकता है
- बजट में इस बारे में अंतिम निर्णय लिए जाने या इस पर अलग से अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है

वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर से रत्न एवं आभूषण समेत ज्यादा रकम वाले लेनदेन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस संबंध में केंद्र सरकार विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है जिनमें ऐसे लेनदेन के साथ आधार कार्ड नंबर या अन्य पहचान संख्या को जोड़ना भी शामिल है।

रत्न एवं आभूषण डीलरों को फिर से प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंडरिंग ऐक्ट (पीएमएलए) की जानकारी देने के लिए पाबंद किए जाने के दायरे में शामिल किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि इस बारे में आरंभिक चर्चाएं हो चुकी हैं और अब अंतिम निर्णय या तो आम बजट में लिया जा सकता है या इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। सभी पैन नंबर को आधार से जोड़े जाने के बाद इस पहल को महत्त्वपूर्ण समझा जा रहा है। चूंकि किसान यह तर्क दे रहे हैं कि उनके पास पैन नंबर नहीं है, इसलिए कई मामलों में उनके द्वारा की जाने वाली खरीदारी को जांच के दायरे में लाने में समस्या पैदा हुई है। ऐसे सौदों को आधार जोड़ने से ज्यादा रकम वाले सभी लेनदेन पर बेहतर तरीके से नजर रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि आधार हर भारतीय के पास है।

ज्यादा रकम के लेनदेन के लिए पैन के बजाय आधार नंबर का इस्तेमाल किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ज्यादा रकम वाले विभिन्न लेनदेन के लिए कई सीमाएं मुहैया कराई गई हैं और इसलिए आभूषण खरीदारी की वैल्यू संपत्ति खरीदारी से अलग है। नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद और 2017 में जीएसटी लागू होने से सभी वाणिज्यिक गतिविधियों पर समन्वित तरीके से नजर रखी जा रही है। लेकिन ज्यादा रकम के लेनदेन पर प्रावधानों पर पुनर्विचार किए जाने और नई सीमाएं तय करने या इन लेनदेन को आईडी प्रूफ से जोड़ने की जरूरत महसूस की गई।

आभूषण समेत कुछ लेनदेन को आधार नंबर से जोड़ना जरूरी है क्योंकि पहले यह पाया गया था कि कुछ विक्रेताओं द्वारा वास्तविक पैन नंबर धारकों द्वारा आभूषण खरीदारी के बगैर ही पैन नंबर का इस्तेमाल किया गया था। आधार कार्ड के लिए भी इस तरह के गलत इस्तेमाल की आशंका को दूर करने के लिए एक ताजा बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें खरीदारी से पहले खरीदार के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर ऐसे इस्तेमाल को प्रमाणित किए जाने पर चर्चा की गई।

पिछले साल 5 जुलाई, 2019 के बजट में सोने, चांदी पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत किया गया था। हालांकि इसका विरोध हुआ था और इसका एक आधार यह था कि इससे सोने-चांदी की तस्करी को बढ़ावा मिलेगा।

सोने की संभावित तस्करी के तर्क की प्रतिक्रिया में सरकार पुराने बहीखाते पुन: खंगाल रही है और रत्न एवं आभूषण डीलरों को फिर से पीएमएलए के अधीन लाने के प्रस्ताव पर काम कर रही है।

अगस्त 2017 में सरकार ने आभूषण उद्योग से ज्यादा रकम के लेनदेन की जानकारी पीएमएलए के अधीन प्राधिकरण को देने को कहा था। हालांकि दो महीने बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया था। उस समय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि इस कदम से विक्रेताओं में इसे लेकर भ्रम बढ़ेगा कि 50,000 रुपये से अधिक के सभी लेनदेन की जानकारी पीएमएलए को देनी होगी। हालांकि सरकार ने इस बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी। सरकार ने यह भी कहा है कि नई सीमा के साथ इसे फिर से लाया जाएगा।

जोखिम से बढ़ेगी सोने की मांग

आर्थिक विकास दर की सुस्त रफ्तार और वैश्विक कारोबारी हालात में बढ़ते तनाव के बीच निवेशकों की पहली पसंद सोना बना है। वर्ष 2020 में मांग बढ़ने के कारण कीमतों में भी इजाफा होगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) ने अपनी नई बाजार रिपोर्ट में कहा है कि बाजार में जोखिम और आर्थिक विकास के बीच अंतर से वर्ष 2020 में सोने की मांग बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2010 के बाद से पिछले साल सोने का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था, जो अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में करीब 18.4 फीसदी था। इसने इसी अवधि में प्रमुख वैश्विक बॉन्ड और उभरते बाजार स्टॉक बेंचमार्क को भी पीछे छोड़ दिया था। अमेरिकी डॉलर और स्विस फ्रैंक को छोड़कर अधिकांश प्रमुख मुद्राओं में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थीं। डब्ल्यूजीसी ने उम्मीद जताई है कि यह चलन 2020 तक जारी रहेगा क्योंकि वैश्विक स्तर पर सोने के लिए समर्थन बना रहेगा। अमेरिकी ब्याज दर में कटौती के साथ संयुक्त वित्तीय और भूराजनीतिक जोखिमों से सोने में निवेश मांग बढ़ने की संभावना है। डब्ल्यूजीसी के अनुसार केंद्रीय बैंकों द्वारा शुद्ध सोने की खरीदारी मजबूत रहने की उम्मीद है। भले ही वह हालिया तिमाहियों में रिकॉर्ड ऊंचाई से कम हों। सट्टा भी सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव को भी बनाए रख सकता है। कमजोर आर्थिक विकास की अस्थिरता और उम्मीदों के परिणामस्वरूप निकट अवधि में उपभोक्ता की मांग में गिरावट आ सकती है, जबकि भारत और चीन में संरचनात्मक आर्थिक सुधार दीर्घकालिक मांग का समर्थन करेंगे । *बीएस*

पाम तेल आयात पर तनाव कम करने की कवायद

मलेशिया करेगा भारत से अधिक चीनी की खरीद!

रॉयटर्स
कुआलालंपुर, 23 जनवरी

- एमएसएम मलेशिया होल्डिंग्स बरहाद पहली तिमाही में 1,30,000 टन कच्ची चीनी की खरीद करेगा
- इसकी लागत 20 करोड़ रिंगिट (4.920 करोड़ डॉलर) आएगी
- कंपनी ने 2019 में भारत से 88,000 टन कच्ची चीनी की खरीद की थी

मलेशिया के शीर्ष चीनी रिफाइनर ने कहा है कि वह भारत से चीनी की खरीद में बढ़ोतरी करेगी। कंपनी के इस निर्णय को इस मामले से जुड़े दो सूत्रों ने पाम तेल आयात पर भारत के साथ चल रहे तनाव को कम करने के प्रयास का हिस्सा बताया है।

एमएसएम मलेशिया होल्डिंग्स बरहाद भारत से पहली तिमाही में 1,30,000 टन कच्ची चीनी की खरीद करेगा जिसकी लागत 20 करोड़ रिंगिट (4.920 करोड़ डॉलर) आएगी। कंपनी ने रॉयटर्स को इसकी जानकारी दी है। 2019 में कंपनी ने भारत से 88,000 टन कच्ची चीनी की खरीद की थी।

एमएसएम दुनिया की सबसे बड़ी पाम तेल उत्पादक एफजीवी होल्डिंग्स की चीनी रिफाइनिंग शाखा है। एफजीवी मलेशिया की सरकारी संस्था फेडरल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या फेल्दा की एक इकाई है।

कंपनी ने चीनी खरीद में बढ़ोतरी के निर्णय को पाम तेल विवाद से संबंधित होने की बात नहीं कही है लेकिन इसको लेकर कंपनी और सरकार के बीच हुई चर्चाओं से अवगत दो सूत्रों ने इसे भारत को तुष्ट करने का प्रयास बताया। कंपनी मलेशिया सरकार से दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे में कमी लाने का अनुरोध कर रही है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल खरीदार है। इस महीने भारत ने कश्मीर के मसले पर मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की आलोचना का प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिकार करने के लिए मलेशिया से पाम तेल के आयात पर प्रभावी तौर पर रोक लगा दी।

पिछले पांच वर्ष से भारत मलेशिया के पाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है।

31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में भारत को मलेशिया का निर्यात 10.8 अरब डॉलर का रहा है जबकि उसका कुल आयात 6.4 अरब डॉलर का रहा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और देश में इसका अतिरिक्त भंडार होने के कारण चीनी के निर्यात में उछाल आई है। 2019-20 के सीजन में निर्यात 50 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है।

इंटरनैशनल शुगर ऑर्गनाइजेशन ऑन रिफिनिटिव एकॉन के आंकड़ों के मुताबिक मलेशिया ने 2019 में 19.5 लाख टन कच्ची चीनी का आयात किया।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Jan 23	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,807.5	5.6	2,062.6	7.5
Copper	6,103.5	5.7	6,524.5	7.1
Nickel	13,645.0	-16.8	14,241.6	-17.2
Lead	1,974.0	-11.7	2,188.9	2.8
Tin	17,575.0	5.2	18,170.3	1.5
Zinc	2,466.5	-1.7	2,609.8	-1.6
Gold ($/ounce)	1,555.1*	4.2	1,739.7	3.6
Silver ($/ounce)	17.7*	0.8	20.0	0.1
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	61.7*	1.9	64.3	6.9
Natural Gas ($/mmBtu)	2.0*	-14.0	1.9	-14.9
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	200.4	14.0	290.9	-4.6
Maize	191.9*	5.0	272.8	-2.8
Sugar	408.9*	22.5	489.5	-0.7
Palm oil	772.5	41.7	1,214.0	37.5
Rubber	1,537.6*	12.6	1,922.3	9.9
Coffee Robusta	1,308.0*	7.9	1,774.9	-7.1
Cotton	1,552.3	8.4	1,616.1	0.0

* As on Jan 23, 20 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.3& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel.
3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	112.9	35131
Oil and Oilseeds	311.5	87442
Spices	0.8	10
Metal(Jan 22)		
Metal- non ferrous	5668.1	50701
Metal- precious	9533.2	421
Oil and gas(Jan 22)		
Gas	2334.5	60398
Oil	13908.3	2068

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	224.8	123535
Grains	109.5	100325
Oil and Oilseeds	533.5	477510
Others	81.4	66555
Pulses	98.1	29345
Spices	46.0	22795

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Natural Gas (Jan 28)	135.9	1.0
Aluminium (May 29)	144.0	0.8
Zinc (May 29)	187.4	0.5
Silver (Mar 05)	46233.0	0.2
Silver Micro (Feb 28)	46254.0	0.2
Silver Mini (Feb 28)	46251.0	0.2
Losers (* % Change)		
Crude Oil (Feb 19)	4048.0	-3.3
Cardamom (Feb 14)	3826.9	-2.5
Zinc Mini (Jan 31)	181.1	-1.7
Mentha Oil (Jan 31)	1220.6	-0.7
Aluminium Mini (Jan 31)	141.1	-0.7
Lead (May 29)	153.0	-0.6

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Jeera Unjha (Mar 20)	14695.0	0.7
Chana-Bikaner (Mar 20)	4111.0	0.5
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Feb 20)	876.2	0.4
Losers (* % Change)		
CottonSeed Oil-Akola (Feb 20)	1956.0	-3.3
Moong-Mertacity (Feb 20)	7525.0	-2.9
Coriander-Kota (Apr 20)	6713.0	-2.0
Guar Seed 10 (Feb 20)	4080.0	-1.0
CastorSeed New-Disa (Feb 20)	4072.0	-0.7
GuarGum 5T-Jodhpur (Feb 20)	7280.0	-0.7
Mustard Seed Rape Oil (Feb 20)	4187.0	-0.6
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1105.5	-0.5
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6216.0	-0.4

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1070.0	2.1
Cotton-Rajkot (Jan 31)	19580.0	1.6
Copper Mum (Jan 31)	452.4	1.3
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	46254.0	1.0
Silver Ahm (Mar 05)	46233.0	0.9
Zinc Mumbai (May 29)	187.4	0.6
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Jan 31)	1220.6	-9.9
Alumini-Mumbai (Jan 31)	141.1	-4.6
Zinc Mini Mumbai (Jan 31)	181.1	-2.7
Aluminium Mum (May 29)	144.0	-2.6
Lead Min Mumbai (Jan 31)	151.6	-2.3
Lead Mum (May 29)	153.0	-1.4

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Mar 20)	6216.0	2.2
Bajra-Jaipur (Feb 20)	1949.0	1.6
Crude Palm Oil Kandl (Jan 31)	784.0	1.0
Maize-Sangli (Feb 20)	1944.0	0.5
Paddy-Basmati-Karnal (Feb 20)	3215.0	0.5
29 mm Cotton-Rajkot (Feb 20)	19380.0	0.3
Discount over spot price (In %)		
Barley Jaipur (Apr 20)	1730.0	-20.7
Jeera Unjha (Mar 20)	14695.0	-5.3
Soy Bean Indore (Feb 20)	4142.0	-3.5
Moong-Merta City (Feb 20)	7525.0	-2.4
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Feb 20)	7280.0	-1.3

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals .....Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg 109.....(109)
Aluminium ingots /kg 147.....(147)
Brass sheet cutting /kg 330.....(333)
Brass utensil scraps/kg 310.....(313)
Copper heavy scrap /kg 432.....(434)
Copper utensil scraps/kg 404.....(405)
Copper wire bar /kg 465.....(466)
Lead ingots /kg 156.....(156)
Nickel Cathodes /kg 1015.....(1040)
Tin slabs /kg 1295.....(1310)
Zinc slabs /kg 186.....(188)
Source:Bombay Metal Exchange

Cotton .....Mumbai
Bengal Deshi /Qtl 10292.....(10292)
DCH - 32 /Qtl 11389.....(11389)
Jaydhar /Qtl 9842.....(9842)
Shankar- 6 /Qtl 11164.....(11164)
Source:Cotton Association of India

Oil .....Mumbai
Castor FSG /10kg 874.....(882)
Castor Comm /10kg 864.....(872)
Ricebran oil/10kg -(820)
Groundnut oil /10kg 1140.....(1140)
Linseed oil /10kg -.....(965)
Karanji /10kg -.....(800)
Palm oil /10kg 860.....(860)
Sunflower exp ref /10kg 900.....(900)
Sunflower oil exp /10kg 860.....(875)
Soyabean ref / 10kg 890.....(895)
Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar .....Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl 3392-3585 .....(3382-3585)
Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel .....
NYSE Crude 55.85.....(56.74)
Brent Crude (UK) 61.78.....(62.17)
Brent Crude (WTI) 56.64.....(56.64)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu 1.94.....(1.91)
Furnace/ 180 Cst &/bbl 334.93.....(333.99)
Naptha spot /Rs/MT 45170.....(45170)
LSHS spot/ M.T. 36150.....(36150)
Furnace Oil spot/ K.L. 33950.....(33950)
Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold .....Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms 39863.....(39916)
Pure (99.90 Purity) /10 gms 40023.....(40076)
Silver.999/ kg 45820.....(46110)
Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	19289.95	19324.10
Alumini-Mumbai (M)	1 K	147.25	147.90
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1950.00	1955.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1939.55	1919.10
Barley Jaipur (N)	1 Q	2178.85	2182.90
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3900.00	3892.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4200.00	4175.00
Castor Seed-Kadi (N)	X	4175.00	4140.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4185.30	4200.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4402.10	4400.00
Chana-Akola (N)	X	4200.00	4137.50
Coriander-Gondal (N)	X	6500.00	6522.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6600.00	6725.00
Coriander-Kota (N)	1 Q	6817.20	6774.60
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2058.50	2046.75
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2025.20	2029.50
Cotton-Kadi (N)	1 B	19266.05	19218.20
CPO-Kandla (M)	10 K	804.90	793.10
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	782.90	776.35
Crude Palm Oil-KAKIN (N)	10 K	790.00	790.00
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	906.15	906.95
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1550.35	1551.70
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3450.30	3454.45
Gold Ahm (M)	10 G	39912.00	39872.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	32058.00	32026.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	4008.00	4002.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7355.55	7375.00
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4042.80	4032.50
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	4025.00	4001.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1130.05	1120.10
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	104.85	105.15
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16250.00	16200.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	15587.50	15510.00
Kachi Ghani Must Oil (N)	10 K	895.00	888.75
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1045.85	1049.80
Kapas-Rajkot (N)	X	1052.45	1056.00
Lead Mum (M)	1 K	154.80	155.20
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1965.00	1956.90
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2285.00	2250.00
Maize-Erode (N)	X	1950.00	1950.00
Maize-Feed/Ind- Gula (N)	1 Q	1451.90	2250.00
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2170.00	2165.00
Maize-Sangli (N)	X	1935.40	1933.65
Masoor Grain Bold In (N)	1 Q	4925.00	4850.00
Moong-Merta City (N)	1 Q	7722.20	7711.10
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4437.00	4411.25
Nickel Mumbai (M)	1 K	1038.20	1016.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3200.00
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3270.00	3252.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	337.80	336.40
Pepper-Kochi (N)	1 Q	33966.65	33600.00
R M Oil-Sriganganaga (N)	X	876.25	862.50
Rape mustards-Patan (I)	20 K	787.00	795.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	1917.00	1910.50
Raw Jute-Kolkatta (N)	X	5325.00	5325.00
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	868.75	865.25
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	900.00	900.00
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	899.25	894.15
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	913.75	908.25
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13700.00	13700.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13708.00	13750.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	46070.00	45807.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4309.00	4293.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4242.00	4242.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4307.65	4343.00
Soy Bean-Akola (N)	X	4246.00	4221.00
Soymeal Indore (N)	1 T	34500.00	34000.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	902.50	901.60
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	31490.00	31600.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	31500.00	31500.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	28480.00	28520.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3275.00	3267.50
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3380.50	3409.50
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3300.00	3300.00
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3447.60	3447.60
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3300.00	3298.15
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3163.15	3162.50
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6077.50	6082.25
Wheat Delhi (N)	1 Q	2200.00	2200.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2181.90	2186.10
Wheat New Indore (N)	1 Q	2205.00	2205.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2080.00	2092.50
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2235.00	2230.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5600.00	5600.00
Yellow Peas-Kanpur (N)	1 Q	5825.00	5800.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	189.40	186.20

* as on Jan 22, 20

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

Name Exchange (Units)

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
DAY SESSION				
दिवस सत्र (गुरुवार)				
कृषि जिंस				
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Jan 31	19700, 19730, 19570, 19580	4668	655	13737
Feb 28	20050, 20050, 19860, 19880	4656	656	18180
Mar 31	20200, 20200, 20130, 20180	306	44	2368
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Feb 20	2025, 2032, 1948, 1956	68650	4236	81800
Mar 20	2048, 2058, 1976, 1984	22450	1653	25330
Apr 20	2079, 2085, 2007, 2016	4590	367	10650
May 20	2107, 2110, 2035, 2040	1610	146	1690
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1118, 1118, 1103, 1105	156	34	824
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1119.5, 1120, 1103, 1105.5	1386	792	4065
Grains				
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	4116, 4122, 4072, 4080	21725	2207	87505
Mar 20	4150, 4164, 4114, 4124	4860	631	9730
Apr 20	4200, 4206, 4174, 4174	100	18	130
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	4100, 4106, 4050, 4072	4195	480	24050
Mar 20	4110, 4110, 4066, 4082	1560	224	9705
Apr 20	4114, 4114, 4080, 4094	715	110	3370
May 20	4128, 4128, 4128, 4128	5	1	5
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Jan 31	796.9, 804.7, 794.5, 796.5	12950	961	31210
Feb 28	786.1, 794.4, 785.5, 786.6	19110	1227	45670
Mar 31	785.5, 788.5, 778, 783.5	3180	245	10040
Apr 30	778, 780, 778, 778.8	30	3	220
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jan 31	1230, 1240, 1214, 1220.6	140.76	312	157.68
Feb 28	1241.9, 1246, 1226, 1230.8	119.88	270	141.48
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4225, 4241, 4172, 4187	9580	808	12320
Apr 20	4270, 4274, 4242, 4265	6680	567	12630
May 20	4276, 4287, 4276, 4286	310	18	1560
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Feb 20	876.8, 881.6, 874.4, 876.2	17420	2028	53145
Mar 20	871, 876.6, 866, 869.2	7955	822	29720
Apr 20	869, 871.4, 863.8, 866.2	200	30	3785
May 20	863.2, 863.2, 863.2, 863.2	10	1	60
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Feb 20	4150, 4172, 4126, 4142	29710	3333	163775
Mar 20	4156, 4172, 4120, 4138	12960	1605	115305
Apr 20	4148, 4186, 4130, 4140	7085	796	42360
May 20	4170, 4190, 4150, 4158	1630	251	5715
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	7330, 7347, 7270, 7280	7180	846	50120
Mar 20	7411, 7440, 7363, 7376	3895	343	16435
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Mar 20	4073, 4149, 4073, 4111	19240	1358	21170
Apr 20	4067, 4124, 4067, 4099	3990	339	6470
May 20	4092, 4150, 4092, 4124	590	51	1640
Jun 19	4180, 4180, 4180, 4180	10	1	20
Moong-Mertacity NCDEX(1 Qtl)				
Feb 20	7525, 7525, 7525, 7525	25	1	25
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Feb 14	3914, 3914, 3808.8, 3826.9	0.9	8	5.5
Mar 13	3800, 3880, 3800, 3844.5	1.2	12	4.1
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Apr 20	6870, 6870, 6700, 6713	2010	190	9600
May 20	6750, 6775, 6748, 6748	90	9	370
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Mar 20	14550, 14770, 14475, 14695	1254	388	1965
Apr 20	14370, 14450, 14250, 14400	498	162	1170
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Mar 20	6178, 6262, 6178, 6216	755	144	4935
Apr 20	6128, 6170, 6106, 6136	255	48	4645
May 20	6238, 6238, 6196, 6196	15	3	110
धातु				
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
May 29	140.55, 140.55, 140.55, 140.55	5	1	6
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Jan 31	141, 141.25, 140.3, 140.5	3103	1876	3093
Feb 28	141.35, 141.35, 140.85, 141.15	1120	667	2203
Copper MCX(1 K)				
Jan 31	452.2, 452.75, 450.6, 450.9	13375	4148	11695
Feb 28	449.2, 450.15, 448, 449.75	1837.5	627	6407.5
Mar 31	448, 449, 448, 448.35	7.5	3	7.5
Lead MCX(1 K)				
May 29	154.5, 154.5, 153.15, 153.85	2	2	8
Lead Mini MCX(1 K)				
Jan 31	152, 152, 151.3, 151.7	3709	2222	3938
Feb 28	152.1, 152.3, 151.75, 152.25	880	621	2277
Mar 31	153, 153, 153, 153	1	1	1
Nickel MCX(1 K)				
Jan 31	1010, 1010.3, 1002.7, 1008.7	12547.5	7667	3720
Feb 28	988.9, 992.6, 982.9, 988.5	1329	792	1578
Zinc MCX(1 K)				
May 29	185.95, 186.1, 185.7, 185.9	8	8	9
Zinc Mini MCX(1 K)				
Jan 31	181.45, 181.85, 180.7, 181.6	16596	9493	11411
Fe

'डेटा निजता मानवाधिकार'

सत्य नाडेला का कहना है कि डेटा निजता की सुरक्षा को प्राथमिकता जरूरी

माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) सत्य नाडेला ने गुरुवार को कहा कि किसी व्यक्ति से जुड़े ब्योरों और सूचनाओं की निजता (डेटा प्राइवेसी) को मानवाधिकार के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे सुरक्षित रखने के साथ-साथ इसमें पूरी पारदर्शिता बरतने की जरूरत है। विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक में नाडेला ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अनुमति के साथ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा डेटा समाज के लिए अच्छा होगा।

उन्होंने कहा कि कहा कि डेटा सुरक्षा का अगला स्तर केवल निजता को बनाए रखना ही नहीं बल्कि लोगों को दुनिया में अपने डेटा इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए सक्षम बनाना भी है। उन्होंने कहा, '2020 के दशक में हमें डेटा सम्मान और नए कारोबारी मॉडल पर काम करने की जरूरत है।' नाडेला ने कहा कि हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को पहले के सॉफ्टवेयर से क्यों हटाया गया।

उन्होंने कहा कि दुनिया सामूहिक तौर पर चार चीजों के जरिये ज्यादा सफलता पा सकती है जो एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनका कहना था, 'तकनीक के इस्तेमाल के जरिये आर्थिक वृद्धि पर जोर देना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि इस वृद्धि का फायदा सबको मिले। तकनीक में भरोसा कायम करना और इसका इस्तेमाल करते हुए इसके दीर्घकालिक भविष्य पर जोर देने जैसे चार अहम बिंदु हैं।'

विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करते माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला

डिजिटल करेंसी पर जोर

डिजिटल करेंसी के लिए बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए विश्व आर्थिक मंच और 40 केंद्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, अकादमिक शोधकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों ने सामूहिक तौर पर इसकी एक रूपरेखा तैयार की है ताकि ऐसी मुद्रा के मूल्यांकन, डिजाइन और संभावनाओं के लिए केंद्रीय बैंकों को मदद दी जा सके। इस रूपरेखा की घोषणा करते हुए विश्व आर्थिक मंच ने कहा कि कंबोडिया के राष्ट्रीय बैंक ने पहले से ही प्रायोगिक स्तर पर अपने राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था के लिए आभासी सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) शुरू किया है। इसके अलावा बहरीन, थाईलैंड और उरुग्वे के केंद्रीय बैंक भी सीबीडीसी मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए टूलकिट का आवेदन दे रहे हैं।

इंटरनेट सुरक्षा के नए उपाय

विश्व आर्थिक मंच ने गुरुवार को इंटरनेट सुरक्षा के नए उपायों की घोषणा की जिसे प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) के समूह और बहुस्तरीय संगठनों ने तैयार किया है ताकि एक अरब उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा दी जा सके। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी 50वीं सालाना बैठक में इस पहल का जिक्र करते हुए कहा कि बीटी, डॉयचे टेलीकॉम, डीयू टेलीकॉम, यूरोपोल, ग्लोबल साइबर अलायंस, इंटरनेट सोसायटी, कोरिया टेलीकॉम, प्रॉक्सिमस, सउदी टेलीकॉम, सिंगटेल, टेलस्ट्रा और आईटीयू ने इन नए उपायों को अपनाया है जिसकी मदद से बड़े साइबर हमलों को रोकने में मदद मिल रही है। इससे 180 देशों के एक अरब उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा मिली है। कुछ साइबर हमले में विशेष संगठनों को निशाना बनाया जाता है जबकि ज्यादातर साइबर हमलों की चपेट में अधिकतर इंटरनेट उपयोगकर्ता आ जाते हैं।

डिजिटल कर समस्या का हल

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के प्रमुख एंगेला गुर्रिया ने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय संस्थान को डिजिटल कर समस्या के समाधान में मदद के लिए 137 देशों का समर्थन मिला है। उनका कहना था कि नए नियमों को लागू करना जरूरी है ताकि अरबों डॉलर की चोरी रोकी जा सके। विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई योजना किसी विशेष डिजिटल कंपनी को लेकर नहीं है बल्कि यह समस्या उन वित्त मंत्रियों से भी जुड़ी है जिनके देश की आमदनी घट रही है। *एजेंसियां*

वैश्विक ब्रांड में एमेजॉन शीर्ष पर

दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) सम्मेलन में बुधवार को जारी हुई ब्रांड फाइनैंस ग्लोबल 500 सूची में ब्रांड एवं रैंकिंग के मामले में एमेजॉन शीर्ष पायजान पर रही। सूची में टाटा समूह ने भारतीय ब्रांडों की अगुआई की और इसके अलावा भारतीय ब्रांड सूची में सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी एलआईसी दूसरे तथा रिलायंस तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि इस बार ग्लोबल 500 सूची में पिछली बार के नौ ब्रांड के मुकाबले इस बार 11 ब्रांड शामिल रहे लेकिन 2020 की सूची भी करीब-करीब पिछली सूची की तरह ही दिखाई दी।

वैश्विक स्तर पर लगातार तीसरी बार शीर्ष पर रहते हुए एमेजॉन ने अंततः 200 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गई। गूगल, ऐपल, माइक्रोसॉफ्ट, सभी पिछली बार की तरह इस बार भी शीर्ष 10 में बनी रहीं। हालांकि रैंकिंग तथा कंपनी मूल्यांकन से इतर कुछ आंकड़ों से थोड़ी उलझन भी पैदा की। ब्रांड फाइनैंस ग्लोबल 500 सूची का कुल मूल्यांकन सालाना आधार पर 2 प्रतिशत से भी कम दर से बढ़ा है। जहां एक तरफ सूची में शामिल 244 ब्रांड के मूल्यांकन में तेजी आई वहीं 212 ब्रांड के मूल्यांकन में कमी आई जिनमें से 95 ब्रांड के मूल्यांकन में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

दूरसंचार क्षेत्र के ब्रांड के मूल्यांकन में भारी गिरावट देखने को मिली है। भारत में भी यह देखने को मिला और एयरटेल सूची में 40 पायदान पीछे खिसक गया। कभी शानदार प्रदर्शन के बदौलत सूची में शामिल होने वाले ब्रांड उबर ने भी गिरावट दर्ज की है, वहीं ईबे सूची के निचले पायदानों पर पहुंच गया। हालांकि शानदार प्रदर्शन करते हुए वॉलमार्ट ने शीर्ष 10 में जगह बनाई है। इसी तरह, पारंपरिक होटलों ने भी वापसी की है। हिल्टन होटल्स ऐंड रिजॉर्ट सबसे तेजी से बढ़ने वाले ब्रांड में शामिल रहा और मैरियट ने भी पिछले एक साल में अच्छी तेजी दर्ज कराई। *बीएस*

एआई, बिग डेटा से बाजार पर नजर रखेगा सेबी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष अजय त्यागी ने गुरुवार को कहा कि पूंजी बाजार नियामक बाजार में गड़बड़ी की आशंका को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पोस्ट की निगरानी तथा उसका विश्लेषण करने के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के तहत कृत्रिम मेधा (एआई), मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स और नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीकों द्वारा हाजिर बाजार में गड़बड़ी पर अंकुश लगाया जाएगा।

मुंबई के समीप पतालगंगा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत 'डेटा लेक' प्रोजेक्ट तैयार करके एनालिटिक्स क्षमताओं का ऑग्मेंटेशन किया जाएगा।

प्रतिभूति बाजार में संभावित जोड़तोड़ को रोकने के लिए सेबी सोशल मीडिया पर नजर रखे हुए है और कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां सोशल मीडिया पोस्ट ने हेरफेर संबंधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई में मदद की है।

त्यागी ने कहा, 'पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके बाजार में गड़बड़ियों का पता लगाना काफी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि ये उपकरण केवल कीमत तथा मात्रा से जुड़े आंकड़े का ही विश्लेषण करते हैं।' उन्होंने कहा, 'हम प्रोद्योगिकी तथा अधिक संख्या में उपलब्ध आंकड़ों का प्रसंस्करण तथा विश्लेषण चाहते हैं, क्योंकि पहले से उपलब्ध संकतिल आंकड़े अधिक मदद नहीं कर पा रहे हैं तथा बाजार में गड़बड़ी करने वाले इनका उपयोग कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन का उपयोग समाशोधन एवं निपटान गतिविधियों में किया जा सकता है। त्यागी ने कहा कि एआई और मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग पूंजी बाजारों में कोष प्रबंधन, व्यापार निगरानी तथा निगरानी कार्यों में बढ़ रहा है।

इन तकनीकों के लिए नियामक ने एक निविदा भी जारी की है। हालांकि सेबी के पास अभी भी सोशल मीडिया पोस्ट और कारोबारी घोषणाओं के विश्लेषण के लिए क्षमताएं मौजूद हैं। ***एजेंसियां***